डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी
रिसर्च फाउंडेशन

श्रमिकों की बात

संपादन

आदर्श तिवारी

रिसर्च एसोसिएट
डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

रिसर्च टीम

अभय सिंह

रिसर्च एसोसिएट
डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

मनुजम पांडेय

रिसर्च एसोसिएट
डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

डिजाइन

अजित कुमार सिंह

अगस्त 2020

**Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation**

9, Ashoka Road, New Delhi- 110001

Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org,

@spmrfoundation

Phone:011-23005850

भूमिका

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लोगों के जीवन की रक्षा के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहसिक निर्णय लेते हुए लॉकडाउन की घोषणा की थी। उसके तुरंत बाद भ्रम की स्थिति में हमारे प्रवासी श्रमिक भाई अपने घरों की तरफ कूच करने लगे। श्रमिकों का इस तरह से पलायन हैरान करने वाला था। गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को बार-बार एडवाईजरी जारी कर श्रमिकों के मुद्दे पर त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए गए। साथ ही, कोई गरीब भूखा न सोए इस संकल्प के साथ सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की भी घोषणा की। इन सब के बीच इस विकट परिस्थिति में भी विपक्षी दल तथा तथाकथित बुद्धिजीवी मानवता को पीछे छोड़ते हुए अनावश्यक रूप से केंद्र सरकार को प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर घेरने की कोशिश में लग गए। दुर्भाग्य से ये लोग दिल्ली में प्रवासी श्रमिकों को एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली से बाहर भेजने तथा महाराष्ट्र के बांद्रा में श्रमिकों को धोखे से गलत सूचना देकर इकट्ठा करने के मुद्दे पर पूरी तरह चुप नजर आए।

बहरहाल, केंद्र सरकार ने श्रमिकों को सुरक्षित घर पहुँचाने के साथ-साथ उनके रोजगार तथा राशन की भी उपलब्धता को सुनिश्चित किया। आंकड़े बताते हैं कि केंद्र सरकार ने 4,594 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से 63 लाख से अधिक श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है। इतना ही नहीं, मनरेगा योजना के तहत 40,000 करोड़ अतिरिक्त राशि आवंटित करते हुए श्रमिकों के गाँव में ही उनके लिए रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। कोरोना संकट के दौरान कोई श्रमिक, कोई गरीब भूखा न रहे, इसके लिए भी मुफ्त अनाज वितरण जैसे कदम उठाए गए तथा 'एक देश एक राशन कार्ड' नामक योजना की शुरुआत की गयी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, गरीब कल्याण रोजगार अभियान हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, केंद्र की भाजपानीत सरकार ने लॉकडाउन की अवधि में इन सभी योजनाओं के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों के जीवन को सरल बनाने की दिशा में कार्य किए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीब और प्रवासी श्रमिकों का विशेष ध्यान रखा। इसमें प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों को किफायती दरों में रहने के लिए छत मिले, इसका प्रबंध किया गया है। रेहड़ी-पटरी वाले भाइयों को मदद करने के लिए भी सरकार ने अपना हाथ बढ़ाया और 5000 करोड़ रूपये आवंटित कर ऋण सुविधा प्रदान की। इसमें रेहड़ी-पटरी वालों को दस हजार रूपये तक के ऋण की व्यवस्था की गई।

समग्रता से देखें तो सरकार ने प्रवासी श्रमिकों से लेकर हर तबके को अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने की कोशिश की है। बावजूद इसके केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसा नैरेटिव गढ़ा गया कि सरकार ने प्रवासी श्रमिकों, गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन, यह बात किसी से छिपी नहीं हैं कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोनाकाल में किए गए सकारात्मक कार्यों की प्रशंसा वैश्विक स्तर पर हो रही है।

बहरहाल, जो श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से घर पहुंचे उन्होंने अपना सुखद अनुभव विभिन्न माध्यमों से साझा किया। श्रमिकों की बातों को सुनकर यह आसानी से समझा जा सकता है कि हमारे श्रमिक/कामगार सरकार द्वारा उनके हितों की दिशा उठाए गए क़दमों से संतुष्ट हैं। इन्हीं सब बातों को सविस्तार समेटते हुए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन द्वारा इस बुकलेट का प्रकाशन किया जा रहा है। इसमें डीडी न्यूज, रेलवे, MyGov एवं अन्य माध्यमों पर आए प्रवासी श्रमिकों की बातचीत के वीडियो एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू की गई रोजगार की नीतियों पर केन्द्रित वरिष्ठ लेखकों एवं शोधार्थियों के आलेख संकलित किए गए हैं। संस्थान सभी संकलित लेखकों के प्रति आभार व्यक्त करता है।

डॉ अनिर्बान गांगुली

निदेशक, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फांउडेशन

विषय सूची

1.	रेलवे के बहाने आपदा काल में राजनीति कर रहे विपक्ष के दावों की श्रमिकों ने खोली पोल - **रमेश कुमार दुबे**	**7**
2.	सुरक्षित और सकुशल घर पहुंचे प्रवासी श्रमिक - **प्रणय कुमार**	**10**
3.	उत्तर प्रदेश लौटकर आए मजदूरों ने उतार दिया कई चैनलों के चेहरे से निष्पक्षता का मुखौटा - **आशीष कुमार अंशु**	**12**
4.	जब से लॉकडाउन में परमिशन मिली है तब से भट्टा चल रहा है - **रूद्र प्रताप दुबे**	**15**
5.	लॉकडाउन में श्रमिकों को घर पहुंचाकर रेलवे ने साबित किया कि वाकई में वो देश की जीवनरेखा है - **लोकेंद्र सिंह**	**17**
6.	कुछ ऐसी घटनाएँ जो इस आपदा काल में पुलिस का मानवीय पक्ष तो दिखाती ही हैं, उम्मीद भी जगाती हैं - **सन्नी कुमार**	**20**
7.	श्रमिक हितों के लिए 'आपदा काल' में भी मोदी सरकार का कामकाज 'आदर्श' रहा है - **पीयूष द्विवेदी**	**22**
8.	कोरोना से लड़ाई में लॉकडाउन का महत्व विपक्ष भले न समझे, मगर आम लोगों ने बखूबी समझ लिया है - **नवोदित सक्तावत**	**26**
9.	श्रमिकों के मुद्दे पर मोदी सरकार ने दिखाई संवेदनशीलता - **अनुराग सिंह**	**28**
10.	कोरोना संकट में श्रमिकों पर राजनीति कर विपक्षी दलों ने अपना असल चरित्र दिखा दिया - **राजीव प्रताप सिंह**	**31**

11. कोरोना जैसी महामारी में भी श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखने में सफल रही मोदी सरकार **- महेश तिवारी** **32**

12. श्रमिकों के लिए भी आपदा को अवसर बनाने में जुटी सरकार **- शिवांशु राय** **36**

13. देश याद रखेगा कि संकटकाल में जब सरकार श्रमिकों के साथ खड़ी थी, विपक्ष संकीर्ण सियासत में लगा था **- सौरभ कुमार** **40**

14. प्रवासी मजदूरों के लिए संजीवनी सिद्ध हो रहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान **- सतीश सिंह** **43**

15. अब जल शक्ति घर लौटे कामगारों का बनेगा आधार **- नेशनलिस्ट टीम** **46**

रेलवे के बहाने आपदा काल में राजनीति कर रहे विपक्ष के दावों की श्रमिकों ने खोली पोल

रमेश कुमार दुबे

भारत में आपदा के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों में तिजोरी भरने के अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे लेकिन आपदा को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की परंपरा विपक्षी दलों द्वारा नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू की गई।

दरअसल प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी आम आदमी के दशकों पुराने लंबित मुद्दों के समाधान में जुट गए। इसका नतीजा यह निकला कि विरोधियों को मोदी को घेरने के लिए मुद्दों का अकाल पड़ गया। इसीलिए उन्होंने कोरोना महामारी के दौर में रेलवे की लेट लतीफी को मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री की घेरेबंदी शुरू कर दी।

गौरतलब है कि आजादी के बाद इतने बड़े पैमाने पर विस्थापन पहली बार हुआ। लॉकडाउन के बावजूद करोड़ों लोग महानगरों-नगरों से अपने गांवों-कस्बों के लिए निकल जाएं तो अफरातफरी मचेगी ही। जिस विपक्ष को आपदा की इस घड़ी में सरकार का साथ देना चाहिए था वह विपक्ष विस्थापितों की तकलीफों को बढ़ाने में जुटा था ताकि मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके। इसे रेलवे के उदाहरण से समझा जा सकता है।

लॉकडाउन के दौरान भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि रेलवे को देश के विभिन्न जिलों को केंद्रित करके बड़े पैमाने पर रेलगाड़ियां चलानी पड़ीं। उदाहरण के लिए 'जन की बात' चैनल के संपादक प्रदीप भंडारी द्वारा ग्राउंड जीरो पर जाकर की गयी बातचीत के एक वीडियो में स्पष्ट होता है कि श्रमिक मोहाली, पंजाब से अमेठी, उत्तर प्रदेश के लिए चलाई गई श्रमिक विशेष ट्रेन से अपने जिले में जा रहे हैं।

वीडियो को देखें तो पता चलता है कि श्रमिकों/कामगारों को व्यवस्थित तरीके से शहर के विभिन्न हिस्सों में एकत्र करके बसों के जरिए मोहाली रेलवे स्टेशन लाया गया और यहां कोरोना से बचाव संबंधी सावधानियों का पालन करते हुए ट्रेन में बैठाया गया। रेलवे के इस व्यवहार से प्रवासी कामगार खुश हैं इसीलिए वे स्थानीय प्रशासन से वादा कर रहे हैं कि जैसे ही हालात सामान्य होंगे वे फिर से आएंगे।

यह तस्वीर उससे एकदम विभिन्न है जिसमें कहा गया कि रेलवे ट्रेनों के संचालन में भेदभाव बरत रहा है और मनमाने ढंग से ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इस आलोचना का विश्लेषण करने पर जो जमीनी हकीकत उभर कर आई वह एकदम अलग है।

1 मई से लेकर 8 जून तक रेलवे ने 4347 श्रमिक विशेष ट्रेनों के जरिए 60 लाख से अधिक लोगों को उनके गंतव्य राज्यों तक पहुंचाया। रेलवे के बहाने प्रधानमंत्री मोदी की घेरेबंदी करने वाले नेताओं ने यह नहीं देखा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे ने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए श्रमिक विशेष ट्रेनों से लोगों को उनके घर तक पहुंचाया। ऐसे समय में जब पूरा देश स्टे होम में हो उस दौर में संक्रमण से बचाव की हर सावधानियां अपनाकर कामगारों को उनके घर तक पहुंचाने का कार्य इतना आसान नहीं था।

चूंकि यह आपदा का समय था इसलिए ट्रेनों का संचालन समान्य परिस्तिथितियों से एकदम अलग ढंग से हुआ। ऐसे में थोड़ी-बहुत अव्यवस्था पैदा होना स्वाभाविक था। फिर अधिकतर ट्रेनों का गंतव्य उत्तर प्रदेश और बिहार था। रेलवे सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ज्यादातर गंतव्य लखनऊ-गोरखपुर सेक्टर के आसपास के थे। बिहार में गंतव्य पटना के आसपास के थे। इन गंतव्यों के लिए ट्रेन की संख्या अत्यधिक बढ़ने के चलते वहां जाने वाले रेल मार्गों पर भीड़भाड़ (कंजेशन) बढ़ गई।

इसके साथ ही, स्टेशनों पर स्वास्थ्य एवं सामाजिक दूरी के विभिन्न नियमों के चलते यात्रियों के ट्रेनों से उतरने में लगने वाला वक्त भी बढ़ा। इसके चलते टर्मिनल पर भीड़ बढ़ी और इससे पटरियों पर दबाव बढ़ गया। इसीलिए कुछ रेलगाड़ियों को उन रूटों पर चलाया गया जो अपेक्षाकृत लंबे थे, जिससे उन्हें गंतव्य स्थान तक पहुंचने में थोड़ी देरी हुई। इसी को लेकर रेलवे संचालन की आलोचना की जाने लगी। लेकिन 'जन की बात' का उक्त वीडियो इस तरह की निराधार आलोचनाओं की हकीकत बयान करता है।

दरअसल लॉकडाउन में मोदी सरकार को देश-दुनिया से मिल रहे समर्थन से मोदी विरोधियों के पास मुद्दों का अकाल पैदा हो गया इसलिए वे रेलवे को बहाना बनाकर मोदी की घेरेबंदी करने लगे। इन व्यावहारिक कठिनाइयों की अनदेखी करते हुए कुछ मोदी विरोधी उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गए। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकारें को निर्देश दिया कि सभी प्रवासी मजदूरों को 15 दिनों के भीतर उनके घर भेजें और उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराएं।

इसके बाद रेलवे ने अपने सामाजिक दायित्व का परिचय देते हुए राज्यों को पत्र लिखकर कहा कि वे प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए श्रमिक विशेष ट्रेनों के लिए मांग पत्र उपलब्ध कराएं, रेलवे चौबीस घंटे के भीतर ट्रेन मुहैया करा देगा। इसके बाद आलोचकों की बोलती बंद हो गई।

समग्रत: मात्र छह वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को मुद्दाविहीन कर दिया। तिसपर इस कोरोना जैसे संकट काल में भी विपक्ष को सरकार के खिलाफ कोई वाजिब मुद्दा नहीं मिल पा रहा, इसीलिए वे सतही विरोध करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में जुटे हैं।

वीडियो लिंक- https://youtu.be/xzVAfAgBoxI

(लेखक केन्द्रीय सचिवालय में अधिकारी हैं। वरिष्ठ टिप्पणीकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

Photo Credit: Times Now

सुरक्षित और सकुशल घर पहुंचे प्रवासी श्रमिक

प्रणय कुमार

अपनों से मिलने की उमंग और उछाह किसमें नहीं होती! भला कौन ऐसा होगा जो किसी आपत्ति-विपत्ति में भागकर अपने परिजनों के पास नहीं पहुँचना चाहेगा! लॉकडाउन में घर को निकल पड़े प्रवासी मजदूरों के मन में कहीं न कहीं यही बात रही होगी।

इस दौरान प्रवासी मजदूरों की ये पीड़ा एवं छटपटाहट कुछ लोगों के लिए जहाँ सचमुच सच्ची सहानुभूति और संवेदना का विषय रही, हिम्मत और हौसला बँधाने की घड़ी रही, तो वहीं कुछ लोगों के लिए यह निहित स्वार्थों की पूर्त्ति का अवसर मात्र था। वे इस संकटकाल में भी मज़दूरों को हिम्मत देने की बजाय उनकी बेचैनी को बढ़ाने, उनमें भगदड़ एवं अनिश्चितता की स्थिति निर्मित करने की साज़िश रच रहे थे।

विस्थापन की पीड़ा को वही समझ सकते हैं, जिन्हें रोजी-रोटी की तलाश में शहर-शहर भटकना पड़ा हो, जिन्हें अपने गाँव-घर, खेत-खलिहान से दूर डब्बों जैसे घरों और तंग गलियों में रातें गुजारनी पड़ी हों, जिनके पाँवों में नगर-डगर नापने के अनुभव और छाले हों। वे नहीं, जो ग़रीबी हटाने और मज़दूरों को हक़ दिलाने के नाम पर कोरी राजनीति करते आए हों।

मजदूरों के बहाने विपक्ष ने सरकार पर खूब निशाना साधा और तरह-तरह के आरोप लगाए। कहा गया कि सरकार उनपर ध्यान नहीं दे रही, उन्हें उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था नहीं हो रही आदि। रेलवे पर भी मजदूरों को ले जाने में बहुत अव्यवस्था और असावधानी बरतने के आरोप लगाए गए। लेकिन सच इन सबसे अलग था और वो समय के साथ जहां-तहां से सामने आ रहा है।

इस संदर्भ में टीवी चैनल न्यूज़ 18 इंडिया का एक वीडियो देखने को मिला. यह वीडियो रिपोर्ट में हिसार, हरियाणा से लगभग 1000 से अधिक श्रमिकों का जत्था बिहार जा रहा है। बातचीत में मजदूर जो बता रहा उसका तात्पर्य यह है कि इस मुश्किल वक्त में रेलवे-प्रशासन ने उनकी बहुत

मदद की। उन्हें सुरक्षित और सकुशल घर पहुँचाने में उनकी व्यवस्था चाक-चौबंद थीं। विपक्ष द्वारा यह आरोप भी लगाया था कि रेलवे मजदूरों से किराया वसूल रहा है, लेकिन इस वीडियो में स्पष्ट है कि मजदूरों से कोई किराया नहीं लिया गया।

इसके अलावा डीडी न्यूज़, राजस्थान के एक वीडियो रिपोर्ट के अनुसार केरल में फँसे श्रमिकों एवं उनके परिजनों को लेकर एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन राजस्थान के हिंडौन शहर पहुँची।

रेलवे ने न केवल उनकी सुरक्षित एवं सकुशल यात्रा सुनिश्चित की, अपितु विभिन्न पड़ावों पर उनके भोजन-पानी का भी यथासंभव प्रबंध किया। उतरने के पश्चात भी उन्हें क्वारन्टीन करने से लेकर उनके घर पहुँचने तक रेलवे के अधिकारी और कार्यकर्त्ता उनकी सेवा में तत्पर रहे।

यह बस कुछ उदाहरण हैं, अन्यथा देश भर के विभिन्न शहरों में फँसे लाखों श्रमिकों को उनके घर तक पहुँचाने में रेलवे की भूमिका स्तुत्य और सराहनीय रही। बल्कि यों कहना चाहिए कि इस संपूर्ण व्यवस्था के सुचारू संचालन में जुटे अधिकारियों-कर्मचारियों ने अपने जान तक की परवाह नहीं की।

जाहिर है, देश में सरकार और सरकारी तंत्र द्वारा मिलजुलकर संकटकालीन परिस्थितियों में भी बड़ी सूझबूझ और योजनाबद्ध तरीके से देश के निर्माणकर्ता श्रमिकों के हितों का ख्याल रखा गया तथा उन्हें सकुशल उनके घर पहुँचाया गया, फिर आरोप लगाने वाले चाहें कुछ भी आरोप लगाते रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

भारत वर्ष की लोकमान्यता जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि की रही है और यदि थोड़ी सकारात्मकता से विचार करें तो इस लॉकडाउन की अवधि में चारों ओर सहयोग एवं सामंजस्य के उदाहरण देखने को मिलते रहे। इस बीच प्रलय के भविष्यवक्ताओं और अराजकता के तमाम सौदागरों के लिए यह बेचैनी और बहस का विषय रहा कि भारत में अमेरिका जैसी लूट-पाट, तोड़-फोड़, मार-काट, उपद्रव-आंदोलन क्यों नहीं हो रहा?

वस्तुतः विखंडनवादी दर्शन के पोषक और अनुयायी भारत के समन्वय और समग्रतावादी दर्शन को कभी समझ ही नहीं पाए। यहाँ राजा भी रंक के द्वार जाता है और रंक भी राजा को पार उतारता है। हम परस्पर पूरकता, सहयोग और सह-अस्तित्व की संस्कृति में विश्वास रखते हैं। हम परहित को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं।

और यही कारण रहा कि चाहे वे सरकारी नुमाइंदे हों या आम जन इस संकट-काल में जिससे

जितना बन पड़ा, उसने जरूरतमंदों की उतनी मदद की। और यही बात मातम के महाभोज की प्रतीक्षा में बैठे कतिपय गिद्धों को रास नहीं आ रही।

वीडियो लिंक - https://youtu.be/1c_phFisxEk

वीडियो लिंक - https://youtu.be/HXAS5rn-V0o

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

उत्तर प्रदेश लौटकर आए मजदूरों ने उतार दिया कई चैनलों के चेहरे से निष्पक्षता का मुखौटा

आशीष कुमार अंशु

इस वक्त पूरी दुनिया संकट से गुजर रही है। सब इस संकट के समय एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं और एक दूसरे को लड़खड़ाने से बचा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच ही देश में बायीं तरफ झुका हुआ कांग्रेसोन्मुख मीडिया का एक तबका, जिनके संबंध में राडिया टेप से पहले समाज में अनुमान से बात होती थी। राडिया टेप ने उस बातचीत के बाद कही—सुनी बात पर विश्वसनीयता की मुहर लगा दी। मतलब खुद को चौथा स्तम्भ कहने वाले वर्ग के कुछ प्रमुख चेहरे राजनीतिक गलियारों में पावर ब्रोकर का काम कर रहे थे।

2014 के बाद कांग्रेस इको सिस्टम के वामपंथी पावर ब्रोकर जर्नलिस्ट्स की पावर सीज हुई है। अब उनका 'ब्रोकर' बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में चैनलों से बाहर निकाल दिए गए कांग्रेस इको सिस्टम के पत्रकारों ने अपना यू ट्यूब चैनल शुरू कर दिया या प्रोपेगेन्डा वेबसाइट की शुरूआत की या फिर चैनल विशेष के माध्यम से फेक न्यूज फैलाने का काम जारी रखा। अपने प्रोपेगेन्डा खबरों को वैधता दिलाने लिए इन्होंने अपने इको सिस्टम से ही एक व्यक्ति को फैक्ट चेक के काम में लगा दिया।

यहां मैं आल्ट न्यूज के प्रतीक सिन्हा की जिक्र कर रहा हूं।

प्रतीक के पिता मुकुल सिन्हा पेशे से वकील थे और खुद को मानवाधिकारवादी कहते थे। गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और खास तौर से नरेन्द्र मोदी से नफरत करने वाले शीर्ष के दस लोगों में वे शामिल थे।

गुजरात दंगों पर तीस्ता सीतलवार और शबनम हाशमी के साथ भी उनका नाम जुड़ता है। मुकुल सिन्हा पूरी जिन्दगी जिस भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते रहे, 2014 में बहुमत से केन्द्र में उसकी सरकार बनते हुए वे नहीं देख पाए। 12 मई 2014 को उनकी मृत्यु हुई।

मुकुल सिन्हा के बेटे प्रतीक भी उनके ही रास्ते पर हैं। उनके पिता जो उनके जीवन आदर्श हैं जिनसे आरएसएस, बीजेपी से नफरत उन्हें विरासत में मिली है। फिर उनके आल्ट न्यूज से निष्पक्षता की उम्मीद भला हम कैसे रख सकते हैं?

इस भूमिका की आवश्यकता यहां इसलिए थी क्योंकि एक दर्शक और पाठक के नाते यह जानने का आपको अधिकार है कि कोरोना के संकट से गुजर रहे देश में मजदूरों के कंधे पर बंदूक रखकर कौन से चैनल और वेबसाइट वाले पत्रकार बायस्ड रिपोर्टिंग कर रहे थे।

जब उन्हें दोनों पक्षों को आपके सामने रखना चाहिए था, वे केवल बदहाली की तस्वीर तलाश रहे थे। अपने रिपोर्टर्स का ऊपर से ही निर्देश दे रहे थे कि सरकार को घेरना है। इस घेरने के दबाव में कई बार रिपोर्टर झूठी खबर भी भेज देता था। जो बाद में फैक्ट चेक में गलत साबित होती थी। उन रिपोर्ट्स को देखते हुए यह साफ हो रहा था कि यह चैनल—वेबसाइट बायस्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

माय गव इंडिया के यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में लगभग आधा दर्जन मजदूरों का अनुभव सुनने को मिला। इस वक्त जब तन्हाई और अवसाद की काली छाया चारों तरफ कोविड 19 के इस दौर में पसरी है, ऐसे समय में यह अनुभव नई ऊर्जा से भर देने वाला है। जब वायर, क्विंट, एनडीटीवी जैसे मीडिया संस्थान मजदूरों के बीच सिर्फ नफरत की बात कर रहे हैं। निराशा फैला रहे हैं। वहीं माय गव इंडिया का विडियो नई रोशनी दिखाने वाला था।

मुम्बई से लखनऊ बस से पहुंचे एक श्रमिक वहां बता रहे हैं कि "यहां पहुंचते ही मुझे निशुल्क भोजन मिला। मास्क और दस्ताने मिले। मुझे बहुत खुशी हुई कि अब मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। मैं बहुत खुश हूं।" ऐसा कहते हुए उनकी खुशी छुप नहीं रही थी। वे काफी प्रसन्न नजर आ रहे थे।

उसी विडियो में रविन्द्र कुमार को सुना। जो लुधियाना में मजदूरी करते थे और वहां से लौटकर,

कहते हैं कि सरकार के पहल के कारण ही मैं वापस लौट कर आ पाया हूं। यहां निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। 1000 रुपए की राशि मिली। और भोजन के साथ राशन सामग्री पाकर मैं बहुत खुश हूं।

ऐसा कुछ अनुभव अजय कुमार मौर्या का भी है। वे मुम्बई कुर्ला से लखनऊ लौटकर आए हैं। उनका कहना है कि वे महाराष्ट्र में फंस गए थे। उप्र सरकार ने उन्हें मुसीबत से निकाला। रास्ते में उनके खाने—पीने का उचित प्रबंध किया। मौर्या अपनी सरकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

यह सच है कि पत्रकार को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। सरकार को उसकी कमियां गिनानी चाहिए। लेकिन विपक्ष होने के लिए विपक्ष की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। यदि एक चैनल, अखबार या वेबसाइट सिर्फ सरकार की आलोचना ही करता हुआ बैठेगा तो उसके पाठक—दर्शक की नजर में उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध होगी।

निष्पक्षता का अर्थ पूर्वाग्रह से भरी हुई रिपोर्टिंग नहीं होती है। निष्पक्षता का अर्थ होता है कि विपक्ष के बयानों के साथ—साथ सरकार के पक्ष से भी जनता को अवगत कराना। बहरहाल लगता तो ऐसा ही है कि कोविड 19 के संकट के दौरान कांग्रेस इको सिस्टम के वामपंथी रुझान वाले खबरिया चैनल—अखबार—यूट्यूब चैनल और वेबसाइट अपना यह धर्म भूल गए थे।

वीडियो लिंक- https://youtu.be/jyBKJYIUCn4

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। लेख में प्रस्तुत विचार पूरी तरह से उनके निजी विचार हैं।)

Photo Credit: Times of India

जब से लॉकडाउन में परमिशन मिली है तब से भट्टा चल रहा है

रूद्र प्रताप दुबे

'बागपत' जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मूल रूप से कभी 'व्यग्रप्रस्थ' अर्थात बाघों की भूमि थी और 1857 के विद्रोह के दौरान तो बागपत ने ये साबित भी किया कि बाघों के साथ ये बहादुरों की भी भूमि है। वर्तमान में इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुख्य व्यावसायिक गतिविधि गुड़ और शुगर मिल हैं। इसके अलावा यहाँ जूते और कृषि उपकरणों के निर्माण में भी कुछ बड़ी इकाइयाँ शामिल हैं।

उस समय, जब उत्तर प्रदेश, दूसरे प्रदेशों में रह रहे अपने श्रमिकों एवं कामगारों की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बन रहा था, तभी 'जन की बात' चैनल के संपादक प्रदीप भण्डारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में श्रमिकों की जमीनी हकीकत और सरकार के दावों की हकीकत को तलाशने पश्चिमी उत्तर प्रदेश निकले।

वीडियो की पहली बातचीत जिसमें प्रदीप द्वारा भट्टा प्रबंधकों से बात की गयी, उस बातचीत में ही एक बात तो स्पष्ट दिख रही थी कि लोग सरकार द्वारा उठाये गये लॉक डाउन के कदम से ना केवल संतुष्ट थे बल्कि योगी सरकार द्वारा प्रत्येक हाथ को काम और हर परिवार को रोजगार देने के मिशन के तहत कामगारों से जुड़ी नीतियों और नियमों में व्यापक सुधार होता भी दिख रहा.

पूरे वीडियो के दौरान 5 अलग-अलग मजदूरों से बेहद स्वाभाविक बातचीत हुई। बातचीत के दौरान प्रदीप के सवाल लगभग एक जैसे रहे जिससे जवाबों के आधार पर वीडियो के आखिर में समस्याओं और सुधारों पर एक परिणाम तक पहुँचा जा सके।

हालांकि अभी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्किल मैपिंग से हर हाथ को काम और हर घर में रोजगार उपलब्ध कराने की कार्रवाई को लगभग अंतिम चरण में पहुँचा दिया है। 11 लाख प्रवासी मजूदरों और श्रमिकों की लिस्ट तो फिक्की और इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जैसे संगठनों से मिल गई है, जिन्होंने

इतनी बड़ी वर्कफोर्स को रोजगार देने का भरोसा दिया है लेकिन जब मजदूरों के पलायन की खबरें राष्ट्रीय फलक पर शुरू ही हुईं थीं, तभी इस विषय पर श्रम शक्ति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी थी।

मजदूरों के साथ अपनी कई वर्चुअल मुलाकातों में मुख्यमंत्री स्पष्ट थे कि प्रदेश सरकार के प्रयास से सभी प्रवासी श्रमिकों/कामगारों को वित्तीय स्थिरता प्राप्त होगी और उनका जीवन यापन दोबारा से सुलभ होगा।

शायद ये सरकार और कामगारों के मध्य का वो विश्वास एवं संवाद ही था जिस कारण इस वीडियो में लखनऊ मुख्यालय से काफी दूर बागपत के एक ईंट भट्टे में हर मजदूर सरकार और भट्टा प्रबंधकों के फैसलों और प्रबंधन से ना केवल पूरी तरह संतुष्ट दिख रहा है बल्कि एक मजदूर ने तो खर्चे के रूप में 3000 रुपये तक मिलने की बात की।

वीडियो के दौरान एक माँग जो निकल के आई वो ये थी कि सरकार भट्टा मालिकों को लगभग एक वर्ष तक का कर्ज प्रदान करे क्योंकि उत्पाद के माँग में बड़ी गिरावट आयी है, इस माँग को केंद्र सरकार ने MSME सेक्टर के अंतर्गत स्वीकार कर लिया है।

समग्र रूप में देखने पर ये वीडियो हमें उत्तर प्रदेश की उस जमीनी वास्तविकता से परिचित कराता है जहाँ सरकार अपने उद्योगों और 'विश्वकर्माओं' का पूरा ध्यान रख रही है। यहाँ श्रमिकों को किसी राज्य की सीमाओं तक छोड़ने की साजिश नहीं है, यहाँ श्रमिक केवल वोट बैंक नहीं है, बल्कि यहाँ पर श्रमिक को सर्वप्रथम एक मानव होने की गरिमा प्राप्त है।

वीडियो लिंक - https://youtu.be/zi_CUwC8p88

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

लॉकडाउन में श्रमिकों को घर पहुंचाकर रेलवे ने साबित किया कि वाकई में वो देश की जीवनरेखा है

लोकेंद्र सिंह

'बा चीन के वुहान शहर से निकलकर पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने अपनी दहशत फैलाकर लोगों को घरों में कैद कर दिया। जनवरी-2020 में कोरोना वायरस ने भारत में अपनी दस्तक दी। भारत में पहला मामला केरल में सामने आया, फिर समय के साथ यह संक्रमण पूरे देश में फैलने लगा।

उधर, दुनिया के विकसित और साधन सम्पन्न देशों- अमेरिका, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन सहित अन्य देशों से भयावह तस्वीरें आना शुरू हो चुकी थीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कोविड-19 (कोरोना वायरस) के पीछे-पीछे ही चल रहा है। उस स्थिति में फौरी तौर पर संक्रमण को रोकने के लिए देश-दुनिया में घरवास (तालाबंदी या लॉकडाउन) ही एकमात्र विकल्प दिखा।

ऐसे में भारत में किसी परिवार के जिम्मेदार और संवेदनशील मुखिया की तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महामारी के प्रकोप से देश को बचाने के लिए 14 अप्रैल को देश में 21 दिन का सम्पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया। इस लॉकडाउन के कारण भारत सरकार को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पर्याप्त तैयारी का अवसर मिला। अगर यह लॉकडाउन घोषित न होता और सफल न रहता तो आज स्थितियां हमारी कल्पना से कहीं अधिक भयावह होतीं।

लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही जो व्यक्ति जहाँ था, वहीं रह गया। लाखों की संख्या में लोग अपने घरों से दूर दूसरे राज्यों में फंस गए। लॉकडाउन के पहले चरण में लोगों ने धैर्य रखा। लेकिन, धीरे-धीरे लोगों के मन में बेचैनी आना शुरू हुई। काम-धंधा न होने से कुछ दिक्कतें भी शुरू होने लगीं। इधर, कोरोना संक्रमण भी लगातार बढ़ ही रहा था। परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद कर उनके परामर्श पर लॉकडाउन-2 की

घोषणा की।

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने सबसे वादा किया कि वे किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, लेकिन देश में ऐसी भी ताकतें सक्रिय हैं, जो हर हाल में भारत को हजार घाव देने का सपना देखती हैं, उन्होंने इस कठिन समय को एक अवसर की तरह देखा और श्रमिक वर्ग के बीच अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया।

उन अफवाहों के कारण श्रमिक वर्ग और अन्य कामगार बस अड्डों एवं रेलवे स्टेशन पर एकत्र होने लगे। जब उन्हें यहाँ कोई साधन नहीं मिले तो वे पैदल ही सड़कों पर अपने घरों की ओर जाते दिखाई देने लगे। इन तस्वीरों को देख कर समूचा भारत समाज द्रवित हो गया और जिससे जो सहयोग बन पड़ा, उन्होंने इन श्रमिकों के लिए किया, जिन्हें प्रवासी मजदूर कहा गया।

भारतीय रेलवे ने साबित किया कि वो देश की जीवनरेखा है

जब विभिन्न राज्यों से श्रमिक एवं कामगार बंधु परिवार सहित अपने गाँव-घर जाने के लिए चल पड़े तो उनकी चिंता के लिए केंद्र सरकार सक्रिय हुई। उन्हें घर तक सुरक्षित पहुँचाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश एवं आवश्यक फंड दिया गया। इसके साथ ही भारत सरकार ने श्रमिक विशेष ट्रेन चलाने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया। एक बार फिर भारतीय रेलवे ने साबित कर दिया कि वह सही मायनों में भारत की जीवनरेखा और भारत के हृदय की धड़कन है।

वरदान बनीं श्रमिक स्पेशल ट्रेनें

मोदी सरकार मजदूरों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए देश में जिन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया, उनमें मजदूरों से कोई किराया नहीं लिया गया। हालाँकि प्रारंभ में किराये को लेकर कुछ गफलत हुई थी, जिसे सरकार ने दूर कर दिया। सरकार ने सिर्फ किराया ही माफ़ नहीं किया बल्कि ट्रेन में श्रमिकों के लिए भोजन-पानी का प्रबंध भी किया गया। मई में देश के अलग-अलग स्टेशनों से मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए श्रमिक एक्सप्रेस रवाना हुईं। जब देश में सभी प्रकार के यातायात साधन बंद थे तब ये श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेने लाखों मजदूरों के लिए वरदान साबित हुईं।

ट्रेन में यात्रियों को दी गई विशेष सुविधाएं

मजदूरों के लिए चलाई गई ट्रेनों में उनके स्वास्थ्य संबंधी सभी तैयारियां की गई थीं। श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से टिकट बुकिंग

की प्रक्रिया चालू की। इस प्रक्रिया में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मजदूर ट्रेन के रवाना होने से कुछ घंटे पूर्व स्टेशन पर पहुँचते। तब स्टेशन पर रेलवे विभाग के कर्मचारियों के द्वारा इन मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण कर एक-एक करके सभी को उनकी बोगियों में बैठा दिया जाता। देश भर से श्रमिकों द्वारा रेलवे एवं सरकार के प्रयासों की सराहना करने वाले वीडियो सामने आए हैं।

जिसमें श्रमिकों से बातचीत से पता चलता है कि यह श्रमिक कई वर्षों से अहमदाबाद में निवासरत थे जो कि लॉकडाउन की वजह से यहीं फंस गए थे। ऐसे में भारतीय रेलवे द्वारा चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन उनके लिए अपने घर तक पहुँचने का माध्यम बन गयी।

मेडिकल चेकअप और भोजन की व्यवस्था

उक्त वीडियो में अहमदाबाद से फिरोजाबाद जा रहीं रीना ने बताया कि वह 20 वर्षों से अहमदाबाद में रहकर एक फैक्ट्री में मजदूरी करती थीं। उन्होंने अपने शहर फिरोजाबाद जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। उन्हें घर से स्टेशन तक लाने के लिए बस की व्यवस्था भी की गयी थी। जब वे स्टेशन पर पहुंची तो यहाँ रेलवे द्वारा उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उनके गंतव्य तक पहुंचने की पूरी व्यवस्था की गई।

इसके साथ ही रीना ने बताया कि रेलवे विभाग द्वारा उनके भोजन का भी पूरा ध्यान रखा गया। एक और यात्री ने बताया कि उसे घर से यहाँ तक लाने की व्यवस्था की गयी है। स्टेशन पर भी ट्रेन में बैठने से पहले स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और रास्ते के लिए भोजन भी दिया गया।

रेलवे विभाग द्वारा श्रमिक यात्रियों के मेडिकल चेकअप की व्यवस्था अहमदाबाद स्टेशन पर की गई थी। कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी यात्रियों को मेडिकल चेकअप के उपरांत ही ट्रेन में बिठाया जा रहा था।

जो भी श्रमिक एवं कामगार इन विशेष ट्रेनों में बैठा, वह बार-बार भारतीय रेलवे को धन्यवाद देता नज़र आया। जाहिर है, भारत सरकार के प्रयासों और रेलवे के सक्रियतापूर्ण और समर्पण के साथ किए गए कार्यों ने लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों की कठिनाइयों को आसान करने में बड़ी भूमिका निभाई है।

वीडियो लिंक - https://youtu.be/J-WOXKZ_67s

(लेखक विश्व संवाद केंद्र, मध्यप्रदेश के कार्यकारी निदेशक हैं। स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

कुछ ऐसी घटनाएँ जो इस आपदा काल में पुलिस का मानवीय पक्ष तो दिखाती ही हैं, उम्मीद भी जगाती हैं

सन्नी कुमार

'बा कोरोना महामारी के इस दौर में जहाँ एक ओर भय और हताशा का माहौल है, वहीं जगह-जगह से ऐसी खबरें भी सुनने को मिलती हैं जो हमारी इस उम्मीद और इच्छाशक्ति को मजबूत करती हैं कि कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। कोरोना को हराने के लिए जहाँ आमलोगों का अभूतपूर्व सहयोग मिला है, वहीं कोरोना वारियर्स के अथक परिश्रम ने पूरे भारतीय जनमानस के अंदर ये विश्वास भरा है कि कोरोना योद्धाओं के रहते उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता है।

इन कोरोना योद्धाओं में जहाँ डॉक्टरों और नर्सों की टीमें अपने जीवन को दांव पर लगा मरीजों की सेवा में दिन रात जुटी हैं, वहीं पूरे भारत वर्ष में पुलिस बल का अभूतपूर्व सहयोगी एवं मानवीय चेहरा सबके सामने आया है।

अपने कंधे पर समाज की सुरक्षा का भार ढोने वाली पुलिस ने अब कोरोना को भी हराने की जिम्मेदारी ले ली है। इसके कारण आज सैंकड़ों पुलिस कर्मियों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है लेकिन इसके बावजूद भी ये खाकी वर्दी धारी योद्धाओं ने अपने आप को कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे अग्रिम पंक्ति में अब तक रखा है। ऐसे कुछ प्रसंगों को साझा करना निश्चित ही इन पुलिसकर्मियों के प्रति सच्चा आभार होगा जो लगातार इस युद्ध में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं।

एक घटना मध्य प्रदेश की है। कर्नाटक से गोरखपुर जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार 'साफिया' तब बेहद परेशान हो गईं जब उन्हें अपनी छोटी बच्ची के लिए कहीं दूध नहीं मिल रहा था। गाड़ी भोपाल स्टेशन पर रुकी हुई थी और वहॉ खड़े आरपीएफ जवान में उन्हें उम्मीद दिखी। इस घटना का वीडियो सबके सामने है.एक बेहद भावुक वीडियो था.

जवान इंदर यादव जब उस छोटी बच्ची के लिए दूध लेने बाहर गए और लौटे तब तक ट्रेन

प्लेटफ़ॉर्म से खुल चुकी थी। इंदर ने प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगाकर उस महिला को दूध पहुंचाया। हम आप शायद इस दौड़ को न समझ पाएँ पर यह साफिया जानती होंगी कि यह कितनी महान दौड़ थी। बाद में उस महिला ने वीडियो पोस्ट कर उस जवान के प्रति अपना आभार भी प्रकट किया।

इसी प्रकार देश के सभी हिस्सों से पुलिस के इस मानवीय स्वरूप की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में असम के डिब्रूगढ़ में एक गरीब सब्जी बेचने वाली महिला को डिब्रूगढ़ पुलिस ने बाइक खरीद कर दिया ताकि वह अपने परिवार के सदस्यों का समुचित भरण पोषण कर सके।

वहीं असम में ही नगांव में अकेले फंसे बुजुर्ग के पी अग्रवाल का जन्मदिन मनाकर सबके बीच यह सन्देश दिया कि पुलिस भी आपके परिवार की ही सदस्य है। निश्चित रूप से इस अपनेपन से इस कठिन दौर में लोगों को संबल मिला और पुलिस जनता के बीच की दूरी कम हुई।

मध्य प्रदेश के इंदौर और जबलपुर में तो सड़क मार्ग से सैंकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर लौट रहे लोगों के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने चप्पलों की व्यवस्था की और उनके लिए नाश्ते और भोजन का प्रबंध किया।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश पुलिस का भी अत्यंत ही मानवीय चेहरा सबके सामने आया है। हाल ही में दिल्ली से सम्भल पैदल जा रहे दम्पति के गोद मे नवजात को देखकर हापुड़ जिले के बाबूगढ़ थाने के इंस्पेक्टर उत्तम सिंह राठौड़ ने उस दम्पति से पैदल जाने का कारण पूछा। दम्पति द्वारा अपनी बेबसी बताए जाने पर इंस्पेक्टर ने उन दोनों को भोजन करवाया और उन्हें घर तक भेजने के लिए बस से जाने का प्रबन्ध किया।

उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे प्रवासी मजदूरों जो दिल्ली या महाराष्ट्र जैसे राज्यों से बेरोजगारी और बेबसी के कारण पैदल ही घर जाने को मजबूर हुए, के लिए किसी देवदूत की भाँति सामने आई है। इस कोरोना महामारी में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहाँ पुलिस के मित्रवत मानवीय चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।

कोरोना के हॉटस्पॉट केंद्रों पर भी पुलिस बलों के द्वारा उतने ही शिद्दत और सत्यनिष्ठा की भावना के साथ लोगों की मदद की जा रही है जिस दौरान कई पुलिस कर्मी रोजाना संक्रमित भी हो जा रहे हैं, फिर भी इनके द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन पूरे निष्ठा और ईमानदारी से किया जा रहा है।

अंत में, ऐसे मुश्किल समय में पुलिस बल जिस सहृदयता से पेश आ रहे हैं, वो ये बताता है कि पुलिस अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रही है। पुलिस पर जो कड़क छवि होने के आरोप

लगते रहे हैं तो उसके पीछे की भूमिका भी इस बार सभी लोगों को समझ में आ रही है कि पुलिस हम आमजन के हितों की रक्षा के लिए अराजक तत्वों के विरुद्ध कड़े रुख अख्तियार करती है, अन्यथा उसका अत्यंत मानवीय पक्ष भी है।

वीडियो लिंक - https://youtu.be/gdirV75tabU

वीडियो लिंक- https://youtu.be/-7qCIpYOZvo

(लेखक इतिहास के अध्येता हैं तथा विभिन्न अखबारों तथा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए लिखते हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

श्रमिक हितों के लिए 'आपदा काल' में भी मोदी सरकार का कामकाज 'आदर्श' रहा है

पीयूष द्विवेदी

24 मार्च को रात आठ बजे राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना महामारी के मद्देनजर इक्कीस दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गयी। यह निर्णय पूरी तरह से सुचिंतित व सुविचारित था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को इस एकदम नए और अपरिचित शत्रु से बचने के लिए व्यावहारिक तथा मानसिक रूप से तैयार करना था। दूसरा उद्देश्य यह था कि भारत जैसे विशाल व सघन आबादी वाले देश में इस आपदा से उपजने वाली संभावित परिस्थितियों के लिए व्यवस्था को तैयार किया जाए।

24 मार्च की घोषणा के बाद 25 से शुरू हुआ लॉकडाउन चार चरणों में होते हुए 31 मई तक चला जिसके बाद एक जून से देश ने अनलॉक की प्रक्रिया में प्रवेश कर लिया जो कि अब भी जारी है।

आज अनलॉक के दौर में आकर हम कह सकते हैं कि सरकार ने जिन उद्देश्यों के साथ लॉकडाउन किया

था, उन्हें प्राप्त कर लिया गया है। 'जान है तो जहान है' से 'जान भी, जहान भी' तक की यात्रा में इस देश ने कोरोना महामारी के साथ जीने का ढंग बखूबी सीख लिया है।

गौर करें तो भारत अपने सामाजिक-आर्थिक स्वरूप में इतना विस्तृत और एक हद तक जटिल देश है कि यहाँ किसी बड़ी समस्या से कितनी और कैसी छोटी-छोटी समस्याएँ पैदा हो जाएंगी, इसका निश्चित पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। समस्याओं का अनुमान हो जाए तो भी उनके समाधान के लिए पूरी तैयारी एकदम से संभव नहीं। लॉकडाउन के बाद श्रमिकों का पलायन एक ऐसी ही समस्या के रूप में सामने आया।

ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन करते हुए केंद्र को दैनिक आय पर निर्भर श्रमिकों का ख्याल नहीं रहा होगा, लेकिन उसे यह उम्मीद भी रही होगी कि राज्य अपने स्तर पर श्रमिकों के लिए समुचित प्रबंध कर लेंगे। कुछ राज्यों ने यह प्रबंध किया भी, परन्तु देश के दो प्रमुख राज्यों, दिल्ली और महाराष्ट्र, की सरकारें श्रमिकों को संभालने में बुरी तरह से नाकाम रहीं।

इनकी नाकामी ने श्रमिक पलायन की समस्या को बहुत बड़ा बना दिया। सिर्फ नाकामी ही नहीं, इन राज्यों में जिस तरह अफवाहों के कारण श्रमिकों का बस अड्डों और स्टेशनों पर जुटान हुआ, उसके पीछे केंद्र के लॉकडाउन को विफल करने की गहरी राजनीतिक साज़िश होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, ने श्रमिकों के पलायन को राजनीतिक मुद्दा बनाने की भरपूर कोशिश की और यह साबित करने के लिए खूब जोर लगाया कि सरकार मजदूरों की चिंता नहीं कर रही। लेकिन ऐसा करते हुए कांग्रेस महाराष्ट्र, जहां वो सत्ता में भागीदार है, की अव्यवस्था के विषय में सन्नाटा मार जाती थी।

महाराष्ट्र के सवाल पर राहुल गांधी यह तक कहते नजर आए कि कांग्रेस महाराष्ट्र सरकार में 'की डिसीजन मेकर' की भूमिका में नहीं है। लेकिन इसपर कुछ नहीं कह सके कि फिर कांग्रेस वहां सरकार में भागीदार बनी क्यों बैठी है?

सिर्फ विपक्ष ही नहीं, मीडिया के एक ख़ास धड़े ने भी पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों की कब्र खोदते हुए श्रमिक पलायन के मसले पर बेहद गैरजिम्मेदाराना रुख दिखाया। एक स्वघोषित जनपक्षधर चैनल के स्वघोषित निष्पक्ष पत्रकार महोदय अपने प्राइम टाइम में जिस तरह श्रमिक पलायन के मुद्दे को उठाते नजर आए उसमें तथ्य कम लच्छेदार बातें अधिक थीं। महाराष्ट्र और दिल्ली से मजदूरों के पलायन पर इन पत्रकार महोदय के मुंह से वहाँ की राज्य सरकारों के लिए सवाल नहीं सुनाई दिए, लेकिन केंद्र को घेरने के मौके वे तलाशते नजर आए।

हम यह नहीं कह रहे कि लॉकडाउन में श्रमिकों के लिए चुनौतियाँ पैदा नहीं हुईं। यह आपदा काल था, सो समस्याएँ होनी ही थीं, लेकिन श्रमिकों की समस्याओं की आड़ में मीडिया के ख़ास धड़ों ने जिस तरह भाजपा और मोदी विरोध का एजेंडा चलाने की कोशिश की, वो उन्हें सवालों के घेरे में लाता है। अब चूंकि यह तो कहीं नहीं लिखा कि कैमरे के सामने खड़े होकर जिस-तिस पर सवाल उठाने वालों की कोई जवाबदेही नहीं होती। बेशक उन्हें सबसे जवाब लेने का अधिकार है, लेकिन सवालों से बाहर वे भी नहीं हैं। सो कुछ जवाब उन्हें भी देने चाहिए।

बहरहाल, दिल्ली और महाराष्ट्र की अव्यवस्था के उलट देश की सर्वाधिक आबादी वाले राज्य यूपी में योगी सरकार के त्वरित निर्णय और सुप्रबंधन के कारण इस तरह की कोई समस्या नहीं हुई। योगी सरकार ने न केवल राज्य में व्यवस्था को चाक-चौबंद कर कोरोना संक्रमण को नियंत्रित रखा बल्कि अन्य राज्यों में फंसे अपने श्रमिकों व छात्रों को वापस लाने का काम भी किया।

यही कारण है कि आज कोरोना संक्रमितों के मामले में दिल्ली और महाराष्ट्र जहां शीर्ष पर हैं, वहीं आबादी में इन दोनों से कहीं अधिक होते हुए भी यूपी काफी नीचे और संभली हुई स्थिति में है।

दिल्ली-महाराष्ट्र जैसे राज्यों की सरकारों ने श्रमिकों के हितों को लेकर सजगता भले न दिखाई हो, परन्तु उनके पलायन को देखते हुए केंद्र ने सक्रियतापूर्वक कदम उठाने का काम किया। श्रमिकों को सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से उनके घर पहुंचाने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का सञ्चालन शुरू किया गया जिसके तहत बीते छः जून तक के आंकड़ों के अनुसार, चार हजार से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के द्वारा देश के अलग-अलग राज्यों से 58 लाख प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुँचाया जा चुका है। निश्चित रूप से अब तक यह आंकड़ा और भी ऊपर पहुँच गया होगा।

आपदा काल में कार्यों के आदर्श रूप में निष्पादित होने की उम्मीद नहीं की जा सकती, परन्तु बावजूद इसके श्रमिकों को घर पहुंचाने की केंद्र सरकार की समुचित व्यवस्थाओं की जो कहानियाँ देशभर के श्रमिकों की जुबानी सामने आई हैं, उनके आधार पर कह सकते हैं कि आपदा में भी नागरिकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कैसे काम किया जाना चाहिए, मोदी सरकार ने इसका आदर्श स्थापित किया है।

'जन की बात' के संस्थापक संपादक प्रदीप भंडारी मोहाली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। वीडियो को देखने से स्पष्ट होता है कि श्रमिकों को बसों के द्वारा स्टेशन लाया गया है। हम देख सकते हैं कि इस दौरान स्टेशन पर सबने मास्क भी लगाए हैं और सोशल डिस्टेन्सिंग का पूरा पालन भी हो रहा है। हम यह भी देखते हैं कि इस पूरी व्यवस्था में जिला प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।

बातचीत में श्रमिक बताते हैं कि वे अमेठी जा रहे हैं और सरकार द्वारा की गयी व्यवस्था से पूर्णतः संतुष्ट हैं। श्रमिक यह भी कह रहे कि जब परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगीं तो वे वापस काम पर पुनः लौटेंगे।

इसी तरह पश्चिम बंगाल, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रवैया कोरोना काल में बेहद गैर-जिम्मेदाराना और संघीय ढाँचे के प्रतिकूल रहा है, से भी केंद्र ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों द्वारा बड़ी मात्रा में श्रमिकों को उनके घर पहुँचाया है। बंगाल के आसनसोल परिक्षेत्र के डीआरएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ वीडियो साझा किए हैं, जिनमें स्पेशल ट्रेनों के द्वारा अपने घर जा रहे लोग रेलवे की व्यवस्था के विषय में बता रहे हैं।

तीस मई को साझा वीडियो में बिहार से आ रहीं एक युवती आसनसोल स्टेशन पर हो रही ट्रेनों की साफ़-सफाई, खाना दिए जाने और रास्ते में आरपीएफ के लोगों के सहयोगी रवैये के विषय में बता रही हैं। चार जून के एक वीडियो में बांद्रा से मुर्शिदाबाद जा रही एक लड़की भी इन सब व्यवस्थाओं की बात करती है।

ये कुछ उदाहरण भर हैं, ऐसे और भी अनेक वीडियो देश भर की अलग-अलग जगहों से आए हैं जिनमें सरकार व रेलवे की व्यवस्थाओं से मजदूर संतुष्ट नजर आ रहे और उनकी सराहना कर रहे हैं। बात केवल घर पहुँचाने तक की ही नहीं है, बल्कि घर पहुँचने के बाद बेरोजगार हो गए मजदूरों को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े इसके लिए भी मोदी सरकार ने लगातार कदम उठाए हैं। खाते में नकदी डालने, मुफ्त राशन, गैस सिलिंडर देने जैसे निर्णय इसका प्रमाण हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, जून तक बीस करोड़ महिलाओं के खाते में कोरोना राहत पैकेज के तहत दो किश्तों में बीस हजार करोड़ से अधिक की धनराशि ट्रांसफर की जा चुकी थी और तीसरी किश्त भेजने का काम भी शुरू हो गया था। इसी तरह अप्रैल से जून के बीच उज्ज्वला के लाभार्थियों को लगभग बारह करोड़ मुफ्त गैस सिलिंडर दिए जा चुके हैं और सितम्बर तक दिए जाने की योजना है।

इसी तरह लोगों को मुफ्त राशन वितरण भी हो रहा है और इस योजना को छठ तक जारी रखने की घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कर चुके हैं। सबसे ख़ास बात ये कि ये सब काम सिर्फ आंकड़ों में नहीं हुए हैं, अपितु धरातल पर भी पहुँचे हैं, जिसकी गवाही श्रमिक स्वयं दे रहे हैं।

समग्रतः श्रमिकों की जुबानी सामने आई ये कहानियाँ न केवल विपक्ष के निराधार आरोपों और एजेंडाधारी मीडिया खेमों की नकारात्मकताओं की कलई खोलती हैं, अपितु मोदी सरकार द्वारा श्रमिक हितों के लिए प्रतिबद्ध भाव से किए जा रहे कार्यों की सच्ची तस्वीर भी प्रस्तुत करती हैं।

वीडियो लिंक – https://youtu.be/xzVAfAgBoxI

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

कोरोना से लड़ाई में लॉकडाउन का महत्व विपक्ष भले न समझे, मगर आम लोगों ने बखूबी समझ लिया है

नवोदित सक्तावत

कोरोना महामारी संकट के चलते हुए लॉकडाउन के चार चरण गुजर जाने के बाद अब देश में अनलॉक का पहला चरण चल रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को पहले लॉकडाउन की घोषणा की थी तब वह एक आपात निर्णय था और कोरोना के तेजी से फैलते संक्रमण से देशवासियों को बचाने का इससे श्रेष्ठ एवं अहम निर्णय दूसरा नहीं हो सकता था।

इसके बाद लगातार दो महीनों तक भय का माहौल रहा। डराने वाले आंकड़े आते रहे लेकिन अब जाकर पिछले एक पखवाड़े में ऐसा लगा है मानो कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई अर्थ पा रही है। स्वास्थय मंत्रालय द्वारा मय आंकड़ों के यह तस्दीक की जा रही है कि देश में अब रिकवरी रेट सुधर रहा है।

मौजूदा संक्रमण के मामलों में से लगभग आधे मरीज स्वस्थ हो चुके हैं एवं शेष आधे एक्टिव केस हैं। इन सब बातों को सुनकर, पढ़कर अब लग रहा है कि मोदी सरकार की दूरदर्शिता एवं कड़ी मेहनत ने देश को एक अभूतपूर्व संकट से बचाया है। यदि समय पर लॉकडाउन लगाने एवं इसको बढ़ाने के सख्त फैसले ना लिए जाते तो भारत की विराट जनसंख्य के मान से मृतकों का आंकड़ा अत्यधिक हो सकता था।

यह साफ़ है कि इस महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन ही बेहतर विकल्प था, जिसके जरिये न केवल संक्रमण की चेन को काफी हद तक तोड़ा जा सका बल्कि तैयारियों के लिए भी सरकार को वक्त मिल गया। लेकिन लॉकडाउन के शुरूआती दौर में देश के विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा जिस तरह इसपर सवाल उठाए गए वो विचित्र ही था।

कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने कहा था कि लॉकडाउन समाधान नहीं है, तो कांग्रेस अध्यक्षा

सोनिया गांधी यह कहती दिखीं कि लॉकडाउन को लेकर सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है। वहीं ममता बनर्जी लॉकडाउन का पालन करवाने को लेकर कभी गंभीर नजर नहीं आईं।

सपा के अखिलेश यादव यह कहते दिखे कि लॉकडाउन से जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं, इसलिए सरकार को विधानसभा का संयुक्त सत्र बुलाकर समस्या के समाधान के लिए विपक्ष से चर्चा करनी चाहिए। जाहिर है, विपक्षी दलों ने लॉकडाउन जैसे बेहद जरूरी निर्णय पर खुलकर सरकार साथ नहीं दिया और जिस-तिस प्रकार इसपर सवाल ही उठाते रहे।

जब विपक्ष यह सब कर रहा था, उसी समय 'जन की बात' के सम्पादक प्रदीप भण्डारी गांवों में जाकर लोगों से लॉकडाउन के औचित्य और उनकी समस्याओं आदि पर बातचीत कर रहे थे। प्रस्तुत वीडियो में प्रदीप उत्तर प्रदेश के सबोदा गाँव के लोगों से लॉकडाउन-2 को लेकर उनकी राय जान रहे तथा लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, इसकी पड़ताल भी कर रहे हैं।

एक वीडियो में शुरुआती बातचीत में जेवर जिले में वाहन चालक के रूप में काम करने वाले ग्रामीण से जब प्रदीप पूछते हैं कि सरकार से मदद मिल रही है, तो जवाब हां होता है। साथ ही उस व्यक्ति का यह भी कहना है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए।

आगे की बातचीत में बुजुर्ग शख्स यह तो मान रहे कि समस्याएँ हैं, लेकिन बावजूद इसके वे लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं तथा मानते हैं कि 'सरकार बढ़िया कर रही है'। जेवर में भवन निर्माण श्रमिक के रूप में काम करने वाले हरेन्द्र कहते हैं कि इस दौरान फिलहाल काम तो बंद है लेकिन संतुष्टि है कि हमें खाने पीने को मिल रहा है। उनकी पत्नी के खाते में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के पैसे आए हैं जिससे आपात समय में भी मदद मिल रही है।

कोरोना के कारण नोएडा से गाँव लौटे एक नौकरीपेशा शख्स का कहना है कि कोरोना जिस तरह की संक्रामक बीमारी है, उसे देखते हुए लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। गांव के लोगों का संयुक्त स्वर यही है कि लॉकडाउन वायरस से लड़ने के लिए ही लगाया गया है और वे इसके समर्थन में हैं। इस बातचीत में यह भी निकलकर आता है कि गाँव में लोग न केवल लॉकडाउन को ठीक मानते हैं, बल्कि उसका पालन भी कर रहे हैं।

वीडियो को देखते हुए समझा जा सकता है कि जब विपक्षी दल लॉकडाउन को लेकर नुक्ताचीनी करने में व्यस्त थे, तब ग्रामीण क्षेत्रों में लोग समस्याओं-परेशानियों के बावजूद लॉकडाउन के पक्ष में थे और सरकार का समर्थन कर रहे थे।

मगर विडंबना ही है कि जो बात देश के गांवों में बसने वाले इन सामान्य लोगों को समझ में आ गयी, वो देश के बड़े विपक्षी दल और उनके प्रबुद्ध नेता अपनी संकीर्ण राजनीति के कारण नहीं समझ सके। ऐसे में, इस वीडियो का यह सन्देश विपक्षी दलों को समझ लेना चाहिए कि कोरोना से लड़ाई में जनता सरकार और उसके निर्णयों के साथ है, वे चाहें जो कहते रहें।

वीडियो लिंक - https://youtu.be/9aq1od-CpDQ

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

श्रमिकों के मुद्दे पर मोदी सरकार ने दिखाई संवेदनशीलता

अनुराग सिंह

बड़ी-बड़ी विपदाएँ धनी-निर्धन, ऊँच-नीच, धार्मिक-जातिगत भेदभावों के बिना सबको प्रभावित करती हैं। ऐसे में हम सबकी ज़िम्मेदारी होती है कि हम एक समाज और देश के रूप में एकजुट होकर इसका सामना करें। संकट यदि समूची मानव जाति पर है, तो यह और भी अधिक गंभीर है।

वर्तमान समय ऐसे ही वैश्विक संकट का समय है। एक जागरूक व्यक्ति और समाज की ऐसे में ज़िम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि हम इसका कैसे डट कर सामना करें। जब सरकारें भी परेशान हैं, सामान्य जन से अधिक से अधिक सहभागिता की अपेक्षा कर रही हैं, तो हमें अपने नागरिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और यदि हम एक संस्था हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है।

बीते दिनों लॉकडाउन के दौरान हुआ श्रमिकों का पलायन वह मुद्दा था जिसपर देश की तमाम विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने सरकार का सहयोग करने के बजाय आरोपों की राजनीति करनी शुरू कर दी। लेकिन जमीन पर न जाने ऐसे कितने ही श्रमिकों की कहानियाँ हैं जो न केवल केंद्र

Photo Credit: rohtasdistrict.com

सरकार की संवेदनशीलता व उत्तरदायित्वों के प्रति सजगता की चर्चा करती हैं बल्कि विपक्ष को आईना भी दिखाती हैं।

सरकार जिसकी कि यह सब ज़िम्मेदारी है, उसने एक संस्थागत ढाँचे के रूप में अपने सभी विभागों के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर बेहतरीन कार्य किया। न जाने ऐसे कितने ही श्रमिकों की कहानियाँ हैं जो एक संवेदनशील सरकार व उसके उत्तरदायित्वों की चर्चा करती हैं। सर्वाधिक श्रमिक उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों से थे। MyGov का एक वीडियो सामने आया जिसमें कई मजदूरों ने अपनी कहानी बताई है।

हैदराबाद में बिहार के राजू कुमार मिश्र लॉकडाउन के कारण फँसे हुए थे। उन्होंने बताया कि एक समय उनके पास खाने तक का राशन नहीं बचा हुआ था, काम ठप होने की वजह से दैनिक कामगारों की रोज़ी-रोटी पर संकट इस समय की गंभीर समस्या थी जिससे राजू भी गुज़र ही रहे थे। उन्होंने पुलिस में जब अपने आप को पंजीकृत किया तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलने के बाद बस की सहायता से इन्हें स्टेशन लाया गया और ट्रेन में बिठाया गया।

राजस्थान से ट्रक में सामान की तरह भर दिए गए मज़दूरों की दुर्घटना में मृत्यु की भयानक घटना हम देख चुके हैं, लेकिन केंद्र द्वारा संचालित रेलवे ने संवेदनशीलता क़ायम रखी। इन लोगों के साथ जिस तरह का मानवोचित व्यवहार होना चाहिए, वैसा हुआ।

सोशल डिसटेंसिंग का पालन हुआ, इनके खाने-पीने का ख़याल रखा गया। सामान्य दिनों में

उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ट्रेनों की स्थिति से यदि आप परिचित हैं, तो राजू कुमार मिश्र के इस भावविह्वल मुद्रा के बयान की आर्द्रता आप महसूस सकते हैं।

हरियाणा के पलवल में काम करने वाले बिहार के लखीसराय जनपद के बृजेश कुमार जो वहाँ पर टाइल्स का काम करते थे, लॉकडाउन में फँसे होने के कारण घर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन रेलवे के इस प्रयास से उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। महाराष्ट्र से परेशान श्रमिकों को जब मध्य प्रदेश में मदद मिली तो उनके ज़ुबान से फूट पड़ा कि मानवता जीवित है।

ये सारे प्रयास सच में मानवता को जीवित रखने के प्रयास हैं। भारत सरकार ने अपने विभिन्न विभागों के साथ सही तालमेल बिठाकर यह सब किया। प्रवासियों की पीड़ा को समझकर उचित समय पर उचित निर्णय ने एक बड़ी आपाधापी को होने से बचा लिया।

उसी समय के न्यूज़ चैनल को आप देखें तो लगातार सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश, सरकार द्वारा मज़दूरों से टिकट का पैसा वसूलने, ट्रेन का 8-9 दिनों में गंतव्य पर पहुँचने जैसी अफ़वाहें देखने को मिलीं जबकि उसी समय रेलवे के दिशानिर्देश को पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा गया कि जिसमें टिकटों के न बेचे जाने का, किराए का 85 प्रतिशत केंद्र सरकार व 15 प्रतिशत गंतव्य स्थल के राज्य द्वारा वहन किया जाना था। रवीश कुमार जैसे पत्रकारों ने बाक़ायदा प्राइम टाइम कर इसे फ़ैलाया कि सरकार पैसा मज़दूरों से वसूल रही है। जबकि सच बिलकुल अलग था।

आजकल एक चलन है कि दिल्ली जैसी सरकारें कम काम का ज़्यादा प्रचार करती हैं और फिर इलाज के लिए राज्य के निवासी होने के दस्तावेज माँगने लगती हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस कार्य को बड़ी शांति से ज़िम्मेदारी पूर्वक संपन्न करने में जुटी रही है। हम सरकारों को इसलिए नहीं चुनते हैं कि वे कोई भी कार्य कर हम पर एहसान जताएँ, अपितु यह उनकी ज़िम्मेदारी है।

भारत एक कल्याणकारी राज्य है जहाँ लोक कल्याण सरकार द्वारा किया ही जाना होता है। ऐसी परिस्थिति में इस सरकार ने बिना किसी लोभ, बिना किसी प्रचार के अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया, एक ज़िम्मेदार सरकार से हम यही उम्मीद कर सकते थे। अफवाह गैंग कुछ भी फैलाती रहे, लेकिन ये पब्लिक है जो सब जानती है।

वीडियो लिंक - https://youtu.be/1Lni4MrHYVI

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं। पत्र-पत्रिकाओं में स्वतंत्र लेखन करते हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

कोरोना संकट में श्रमिकों पर राजनीति कर विपक्षी दलों ने अपना असल चरित्र दिखा दिया

▸ राजीव प्रताप सिंह

एक उक्ति हम हमेशा ही सुनते रहे हैं कि कठिन समय में ही व्यक्ति की विश्वसनीयता की पहचान होती है। कोविड संकट के दौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस संकट ने भारतीय राजनीति में अनेक राजनीतिक दलों के असल चरित्र को बेपर्दा कर दिया। एक तरफ जहाँ पूरी मानव सभ्यता के ऊपर इस संकट में सामान्य नागरिक से उत्तरदायित्वबोध की अपेक्षा की जा रही है, वहीं कुछ राजनीतिक दलों ने आपदा के इस इस दौर में भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का ही काम किया है।

इसका ज्वलंत उदाहरण हम लॉकडाउन के आरंभिक समय में एक प्रमुख विपक्षी दल के मुखिया के गैर जिम्मेदाराना बयान के बाद मुंबई में एक रेलवे स्टेशन पर श्रमिकों के हजारों की संख्या में इकठ्ठा होने के रूप में देखते हैं। दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार के कुप्रबंधन व अफवाह तन्त्र के कारण आनंद विहार बस अड्डे पर भारी भीड़ इकट्ठी हो गयी थी। कांग्रेस और इसके शीर्ष नेताओं की नकारात्मक राजनीति तो हम देख ही शुरू से ही देख रहे हैं।

ऐसे में सवाल है कि आपदा के इस दौर में क्या देश के विपक्षी दलों को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझनी चाहिए? क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की ही है?

अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई के एक शोध पत्र के अनुसार भारत में अनेक लोक कल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंदों तक सिर्फ इसलिए नहीं पहुँच पाती हैं, क्योंकि अपनी राजनीतिक पहचान (पहचान पत्र या निवास का पता) के अभाव में वे सरकार की नीतियों का हिस्सा नहीं बन पाते हैं।

मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही ऐसी अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर लेकर आई, जो इन जरुरतमंद लोगों को मुख्यधारा में ला सकें और उनको भी सरकारी नीतियों का

Photo Credit: news.gangapur.city

हिस्सा बना सकें। चाहें वह जन-धन योजना हो, डिजिटल इंडिया हो या अनेक ऐसी अन्य योजनाएं हों।

कोरोना संक्रमण के इस दौर में जब स्वाभाविक तौर पर सरकार की जिम्मेदारी बढ़ गयी है, ऐसे में सरकार ने अनेक क्षेत्रों में, अनेक राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया। लेकिन कुछ राज्य सरकारें राजनीति से बाज नहीं आईं।

फिर भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की बात हो, जरुरतमंदों के खातों में सीधे तौर पर आर्थिक मदद की बात हो या अनेक राज्यों में फंसे विद्यार्थियों को उनके गृह राज्यों में पहुँचाने की बात हो एवं इसके साथ ही एक राशन कार्ड से पूरे देश में राशन प्रदान करने की योजना हो, प्रत्येक योजना के द्वारा सरकार ने गरीब श्रमिकों तक पहुँचने का प्रयास किया और उनकी समस्याओं को कम करने का काम किया है।

1 मई से 9 जुलाई के बीच रेल मंत्रालय ने 4165 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलवाईं, जिसमें 63 लाख लोगों को अपने गृह राज्यों में भेजने का काम किया। श्रमिकों के लिए इस योजना में रेल मंत्रालय ने कहा कि टिकट का 85 फीसदी खर्च केंद्र स्वयं वहन करेगा और अन्य 15 फीसदी सम्बंधित राज्य सरकारें वहन करेंगी, लेकिन देश के बड़े मीडिया संस्थानों ने इसको बिलकुल अलग तरह से रिपोर्ट किया, जिससे बाद में उनकी किरकिरी भी हुई। अनेक कथित पत्रकारों ने तो अपने-अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अफवाह फ़ैलाने तक का काम किया।

इन सब के बावजूद आज अनेक ऐसे अनुभव हम अपने आसपास देख सुन सकते हैं, जो इन सभी नकारात्मकताओं के बीच एक सकारात्मक भाव पैदा करते हैं और सरकार की नीतियों से सामान्य जन को मिले लाभ को दर्शाते हैं। इसकी बानगी हमें सोशल मीडिया पर विभिन्न समाचार चैनलों, रेलवे के

सोशल मीडिया हैंडल और डीडी न्यूज के माध्यम से आ रही वीडियो स्टोरी से देखने को मिलती है-

ऐसे ही एक वीडियो हमारे नजर में आया जिसमें कई मजदूर अपनी आपबीती या कहें तो अनुभव साझा कर रहे हैं. अहमदाबाद में फिरोजाबाद के कई अन्य मजदूर जो लॉक डाउन के कारण फंसे हुए थे, वे विगत 15 वर्षों से अहमदाबाद में रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि खाने पीने की अच्छी व्यवस्था की गई है और लॉक डाउन में फंसे मजदूरों को घर पंहुचाया जा रहा है। आगे बताते हैं कि उनको ट्रेन के समय से पहले बुलाकर उनका मेडिकल चेकअप किया गया। ट्रेन के समय के अनुसार बसों से हमें स्टेशन पहुँचाया गया। अब हम लोग ट्रेन के अन्दर बैठे हैं और अब कोई समस्या नहीं हैं।

विद्यानगर, अहमदाबाद में काम करने वाले दिनेश कुमार यादव बताते हैं कि उनका पहले ऑनलाइन पंजीयन हुआ था फिर उनका मेडिकल चेकअप भी हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले बहुत चिंता हो रही थी लेकिन सरकार ने बहुत सहूलियत के साथ उनको बसों से स्टेशन छोड़ा और अब वे अपने गृह प्रदेश जा रहे हैं।

श्रमिकों से हुई इस बातचीत से स्पष्ट है कि रेलवे ने स्टेशन तक पंहुचाने से लेकर मेडिकल चेकअप तथा खाने पीने तक का प्रबंध किया था। ट्रेनों में बैठने से पूर्व वे श्रमिक परेशान अवश्य थे, लेकिन ट्रेनों में बैठने के बाद उन्होंने राहत की साँस ली। यह चीजें इस आपदाकाल में भी केंद्र सरकार के सुप्रबंधन की ही कहानी कह रही हैं, लेकिन अंध-विरोध को ही अपनी राजनीति का मूल बना चुके विपक्षी दलों का रुख इस दौर में उत्तरदायित्वशून्य और निराशाजनक रहा है।

वस्तुतः इस संकट के दौर में सभी को व्यक्तिगत तौर से अपनी जिम्मेदारी समझने के साथ-साथ विपक्षी दलों को भी सरकार के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों को केंद्र सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करके उनका सहयोग करने की जरुरत है। सरकारों के आपसी समन्वय से ही इस आपदा से बेहतर ढंग से लड़ा जा सकता है।

केंद्र सरकार और यूपी सरकार का तालमेल इस विषय में आदर्श कहा जा सकता है और यह बड़ा कारण है कि यूपी में कोरोना संक्रमण की स्थिति अब भी नियंत्रण में है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि राज्यों को भी इससे प्रेरणा लेते हुए, अपनी दलीय राजनीति को विराम देकर, केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहिए। समय की यही मांग है।

वीडियो लिंक - https://youtu.be/J-WOXKZ_67s

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

कोरोना जैसी महामारी में भी श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखने में सफल रही मोदी सरकार

महेश तिवारी

हमें आज़ाद हुए सात दशक से अधिक समय हो चुका है, लेकिन इस दौरान की अधिकतर पूर्ववर्ती सरकारों का जनता को लेकर रवैया ऐसा रहा कि सरकारी तंत्र से कोई उम्मीद रखना ही देश की अवाम छोड़ चुकी थी। लेकिन पिछले छह वर्षों में देश में काफ़ी बदलाव हुए हैं, न सिर्फ़ राजनैतिक लिहाज़ से बल्कि सरकार के प्रति जनता के मिज़ाज में भी।

मोदी सरकार ने पिछले छह सालों में "सबका साथ- सबका विकास" के नारे के साथ जनकल्याण के जो कार्य किए हैं, उन्हें देखते हुए विपक्ष मुद्दाविहीन और हताश हो चुका है। सच पूछिए तो विपक्षी दलों की चूलें हिल चुकी हैं। इसी कारण अब विपक्ष अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए विपदा के समय में भी सरकार का साथ देने के बजाय उसकी नाकामी गिनाने में लगा हुआ है।

कोरोना जैसी वैश्विक समस्या पहले तो कभी आई नहीं थी। फ़िर भी मोदी सरकार ने न केवल इस आपदा से बचाव के लिए शानदार ढंग से काम किया है, बल्कि इसे अवसर में तब्दील करने में भी जी-जान से जुटी हुई है। वहीं देश के विपक्षी दल हैं जो सिर्फ़ विरोध का बेसुरा राग अलाप कर अपने होने का अहसास करा रहे हैं।

यह ठीक है कि लॉकडाउन के दौरान कई प्रकार की समस्याएं सभी को आईं, लेकिन उन्हें दूर करने का जो माद्दा मोदी सरकार ने दिखाया शायद कांग्रेस की किसी पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कोरोना जैसी आपदा की स्थिति में ऐसे प्रबंधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

लॉकडाउन के दौरान जब मोदी सरकार ने सभी को सुरक्षित करने और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए ताली और थाली बजाकर कोरोना वॉरियर्स का समर्थन करने को कहा, तो उसे भी विपक्ष ने सरकार की सनक करार दिया, लेकिन कहीं न कहीं मोदी सरकार की दूरदृष्टि और

सकारात्मक सोच का परिणाम ही रहा कि आज कोरोना से लड़ाई में हम अच्छी स्थिति में है।

जब मोदी सरकार ने कोरोना से लोगों की जान बचाने तथा आवश्यक तैयारिया करने के लिए लॉकडाउन का निर्णय लिया तो श्रमिकों के पलायन की एक समस्या सामने आई। तब विपक्ष ने शिगूफा छोड़ा कि श्रमिकों की सुध सरकार नहीं ले रही।

लेकिन विपक्ष के आरोपों से अलग सरकार श्रमिकों को सकुशल घर भेजने की समुचित व्यवस्था बनाने और फिर उसको क्रियान्वित करने में जुटी रही। फ़िर विपक्ष ने आरोप लगाया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में श्रमिक वर्ग को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, इसमें पानी-दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है।

विपक्ष के इन आरोपों की सच्चाई धीरे-धीरे देश के सामने आ गयी जब विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिये श्रमिकों ने सरकार के सुप्रबंधन की सराहना की। दैनिक भास्कर द्वारा प्रस्तुत ये वीडियो इंदौर रेलवे स्टेशन का है जिसमें एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लोगों से बातचीत की गई है। यह ट्रेन पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के लिए रवाना हुई 1250 लोगों को लेकर।

इसमें बैठे अधिकतर यात्री न सिर्फ़ इंदौर का गुणगान कर रहे, अपितु मोदी सरकार की नीतियों को राज्य में फलीभूत करने वाले भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ़ भी कर रहे हैं। वीडियो में राजकुमार विश्वास नामक व्यक्ति कह रहे कि शिवराज सिंह जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और हम लोगों को अपने घर वालों से मिलाने की व्यवस्था की है।

मालदा डीआरएम के ट्विटर हैंडल साझा ये दूसरी वीडियो पश्चिम बंगाल के मालदा स्टेशन की है। जहां पर यात्री श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की सुविधाओं से बेहद ख़ुश नजर आ रहे। वीडियो में यह भी साफ़ देखा जा सकता है कि कैसे विधिवत तरीके से ट्रेन की सफ़ाई वगैरह हो रही। इसके अलावा जब रेलवे के कर्मचारियों ने मालदा स्टेशन पर यात्रियों से ट्रेन की सुविधाओं के बारे में पूछा तो सभी बेहद सन्तुष्ट नजर आए।

एक यात्री ने रेलवे कर्मचारी को बताया कि वह बैंगलोर से आ रहा और त्रिपुरा तक जाएगा। मालदा स्टेशन पर मिली सुविधाओं से वह काफ़ी ख़ुश नजर आया। उसने बताया कि मालदा में ट्रेन की विधिवत सफ़ाई और भोजन पानी का बेहतरीन इंतजाम रहा।

तीसरा वीडियो भी मालदा डीआरएम के ट्विटर हैंडल का ही है, जिसमें ट्रेन में बैठी महिला यात्रियों से जब रेलवे कर्मचारियों ने सवाल किया कि वे कहाँ से आ रही हैं और सुविधाएं कैसी हैं,

तो उनका जवाब था कि वे त्रिपुरा से बिहार के नवादा जा रही हैं। साथ ही, महिला यात्रियों ने रेलवे की साफ़-सफाई और व्यवस्थाओं को लेकर भी ख़ुशी ज़ाहिर की।

इसके बाद एक अन्य यात्री से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि वह उदयपुर से चलकर बिहार के गया जा रहा। उक्त यात्री भी रेलवे की सुविधाओं के प्रति खुश नजर आया। इसके अलावा मालदा डीआरएम के ट्विटर हैंडल पर ऐसे अन्य कई वीडियो भी मिल जाएंगे, जिनमें साफ़ दिख रहा कि स्पेशल ट्रेनों में रेलवे की सुविधाएं कितनी बेहतर हैं।

स्पष्ट है कि कोरोना जैसे संकट में भी मोदी सरकार के बेहतर कामकाज के कारण विपक्ष बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में वो सरकार पर ऊल-जुलूल आरोप लगा रहा। लेकिन विपक्ष को समझ लेना चाहिए कि जनता सब जानती है। वह अब झांसे में नहीं आने वाली क्योंकि अब उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में विकास की राह दिखाने वाला एक मजबूत नेता मिल गया है।

वीडियो लिंक - https://twitter.com/i/status/1262048972811706368

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

श्रमिकों के लिए भी आपदा को अवसर बनाने में जुटी सरकार

शिवांशु राय

हबीते दिनों रेल मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए डीडी न्यूज़ के एक वीडियो में मध्य प्रदेश के सतना जिले की एक रोचक घटना सामने आई। हुआ ये कि जिले की उचेहरा जनपद की ग्राम पंचायत जिगनहट के श्रमिक रोजी-रोटी कमाने की तलाश में महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व प्रदेश के अन्य जिलों में गए थे।

कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन होने पर गांव के करीब 87 श्रमिक वापस लौटे। इन्हीं श्रमिकों में से 12 श्रमिकों ने स्कूल में अपनी अनूठी कला का प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने क्वारंटाइन अवधि के दौरान

क्वारंटाइन सेंटर के रूप में विकसित शासकीय माध्यमिक शाला जिगनहट को वंदे भारत एक्सप्रेस का रूप दे दिया।

यह खबर देश भर में प्रेरणा का स्रोत बनी थी और यह साफ सन्देश गया कि हुनर और प्रतिभा के पलायन को रोक कर किसी भी क्षेत्र की बदतर स्थिति का कायाकल्प किया जा सकता है।

भारतीय रेलवे ने इसी से प्रेरणा लेते हुए तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए देश भर में प्रवासी मजदूरों को मनरेगा तथा गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत काम देना शुरू किया। इस अभियान के तहत रेलवे ने बिहार के खगड़िया, बेगूसराय, गया तथा मधुबनी में अनेक प्रोजेक्ट में काम दिया। भारतीय रेल ने मनरेगा योजना की मदद से मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने स्थानीय प्रशासन की मदद से बड़ी संख्या में रोजगार दिया है।

गौरतलब है कि रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 160 प्रोजेक्टों में 9 लाख श्रम दिवस के बराबर रोजगार देने की एलान किया था जो बड़े स्तर पर प्रवासी मजदूरों के लिए राहत भर फैसला था।

भारतीय रेलवे ने एकबार फिर संकट की घड़ी में देश को संभाला। श्रमिकों की घर वापसी के साथ-साथ रेलवे ने अपने रेल डिब्बों को अस्थायी कोविड केअर कोच में तब्दील किया साथ ही मजदूरों को रोजगार प्रदान कर दुनिया मे अलग ही मिसाल कायम की।

यह सत्य है कि कोरोना महामारी के कारण देश के श्रमिक वर्ग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और अप्रैल-मई माह के दौरान एक समय ऐसा लगने लगा था कि देश भर में शहरों से गांवों की तरफ प्रवासी मजदूरों के 'रिवर्स माइग्रेशन' से बेरोजगारी, खाद्यान्न समस्या, गरीबी और जीवन निर्वहन सम्बन्धी समस्याएं लंबे समय तक बनी रहेंगी और भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा।

लेकिन केंद्र सरकार ने उचित समय पर इस 'आपदा को अवसर' में बदलते हुए 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की शुरुआत की और साथ ही साथ श्रमिकों, गरीबों और वंचित समूहों के लिए 'आर्थिक पैकेज' में रोजगार, खाद्यान्न और आर्थिक सहायता सहित स्वास्थ्य सुविधाओं का भी एलान किया जिससे स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सका है।

संकट के बीच कल्याणकारी राज्य की भावना के अनुरूप तथा समतामूलक समाज की दृष्टि से सरकार ने जनता के 'जीवन जीने के अधिकारों' को भलीभांति पूरा करने हेतु सभी राज्यो के साथ मिलकर 'सहकारी संघवाद' का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है।

हमारे देश की लाइफलाइन कहे जाने वाले श्रमिक वर्ग की श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से घर वापसी के बाद उन्हें डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहयोग, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से प्रत्येक महीने मुफ्त राशन तथा वन नेशन, वन राशन कार्ड की सुविधा, पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान तथा मनरेगा में रोजगार सृजन, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लघु ऋण सुविधा तथा शहरों में श्रमिकों और निर्धनों को वहनीय किराए के आवासीय परिसर उपलब्ध कराने जैसी अनेक लोककल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया।

इसके साथ-साथ विशाल मात्रा में श्रम शक्ति का उपयोग करने की योजना के साथ 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से देश को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बनाने के विजन की दिशा में बढ़ा जा रहा है।

लॉकडाउन के समय श्रमिकों के पलायन से उपज रही अनेक समस्याओं से निपटने का एक सबसे प्रभावी उपाय यही नजर आ रहा था कि बेहतर कार्ययोजना तैयार कर उन्हें अवसरों में बदला जाए और सरकार ने ऐसा ही किया।

दरअसल ग्रामीण भारत में छोटी जोत वाली कृषि, बढ़ती बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आधारभूत सुविधाओं की कमी ही कमजोर तबके के लोगों को शहरों में संगठित और असंगठित क्षेत्रो में मेहनत-मजदूरी करने के लिए मजबूर करती है। यह सत्य है कि स्थानीय स्तर पर टिकाऊ और लाभप्रद रोजगार मिलने से ये पलायन की समस्या रुक सकती है और शहरों में बढ़ती जनसंख्या, अनियंत्रित-अनियोजित और निम्न स्तर के रहन-सहन में सुधार देखने को मिल सकता है।

आईएलओ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत मे 90 फीसदी यानी 43 करोड़ के आस-पास मजदूर असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं जो कोरोना काल में सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं और सरकार का इन्ही वर्गों पर ध्यान है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि कोरोना के प्रकोप के पहले इनसे सम्बंधित ठोस डेटा, कार्यक्षेत्र की जानकारी और नियामकीय ढांचा का अभाव था, जिसे अब सरकार ने युद्ध स्तर पर लगकर तैयार किया है।

सरकार अब उन्हें उनके हुनर, दक्षता और जानकारी के आधार पर स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया करा रही है। हिंदी पट्टी के राज्य जहां सबसे अधिक श्रमिकों का आगमन देखने को मिला है, वे इसे अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रहे हैं।

इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, बड़े स्तर पर वापस लौटे श्रमिकों के हुनर को पहचान कर

उन्हें रोजगार देने के प्रयास में अब तक 23 लाख से अधिक श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम पूरा कर चुकी है। इन्हें 94 कैटेगरी में मापा गया है तथा रोजगार के लिए एमएसएमई सेक्टर से जोड़ा जाएगा।

गौरतलब है कि सरकार अर्थव्यवस्था के रफ्तार देने के लिए एमएसएमई सेक्टर को बड़े आर्थिक पैकेज देकर प्रोत्साहन देने में लगी है। विपक्ष की तमाम आलोचनाओं के बावजूद सरकार कृषि सम्बन्धी क्षेत्रों में लघुकालीन तथा दीर्घकालिक योजनाएं बनाकर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन, सब्जी, बागवानी, मत्स्यपालन, औऱ मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित कर कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन दे रही है। इससे यह साफ सन्देश जाता है कि सरकार कृषि को लेकर 'घाटे का सौदा' सम्बंधित स्थापित धारणा को बदलना चाहती है।

सरकार कृषि और एमएसएमई सेक्टर को सस्ते ऋण उपलब्ध कराकर तथा तय एमएसपी पर फसल खरीद को प्रोत्साहित कर ग्रामीण क्षेत्रों में आय का जरिया सुनिश्चित कर अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने पर जोर दे रही है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी कल्याणकारी और दूरदर्शी योजना के माध्यम से अनेक आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा प्रत्येक उत्पादन क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के साथ साथ नवाचारों औऱ प्रौद्योगिकी पर जोर देकर दुनिया में सप्लाई चेन के रूप में भारत को विकसित करने पर जोर दे रही है।

जाहिर हैं देश को सुदृढ़, आत्मनिर्भर बनाने तथा कोरोना काल के बाद अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए श्रमिकों के श्रम बल को बेहतर तरीके से उनके हुनर और कार्यकुशलता के अनुसार उपयोग करने की जरूरत है जिसमें राज्यों को केंद्र को पूर्णतः सहयोग देने की आवश्यकता है।

पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व युवा कौशल दिवस पर कौशल उन्नयन के लिए तीन मंत्र 'स्किल, री-स्किल, अपस्किल' देते हुए कहा कि कोविड-19 ने नौकरियों की प्रकृति को बदल दिया है और हमे समयानुसार परिवर्तित होना पड़ेगा।

हमे यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भारत जैसे देश में आपदा की स्थिति में ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने ही देश को संभाला है और सरकार की योजनाएं भी ग्रामीण विकास पर केंद्रित हैं, ऐसे में वापस लौटे श्रमिको को स्थानीय स्तर पर उनके हुनर को पहचान कर रोजगार देने से देश के विकास में फैली असमानताओं को खत्म करने में मदद मिलेगी और सरकार भी इसी दिशा में बढ़ रही है।

वीडियो लिंक - https://twitter.com/i/status/1282268353583656961

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

देश याद रखेगा कि संकटकाल में जब सरकार श्रमिकों के साथ खड़ी थी, विपक्ष संकीर्ण सियासत में लगा था

सौरभ कुमार

कोरोना की महामारी से देश अब धीरे-धीरे उबरने लगा है। मामले जरूर अब भी आ रहे, लेकिन अब इस महामारी के साथ जीने की आदत लोगों ने विकसित कर ली है। बाजार और दफ्तर खुल गए हैं और लोग घरों से बाहर भी निकलने लगे हैं।

आज से दशकों बाद भी जब भारत में कोरोना के काल को याद किया जायेगा तो शायद आँखों के सामने जो तस्वीर सबसे पहले आएगी वो अस्पतालों और पीपीई किट पहने स्वास्थ्य कर्मियों की नहीं, बल्कि सैकड़ों की संख्या में पलायन कर रहे मजदूरों की होगी।

लॉकडाउन की घोषणा के कुछ दिनों के बाद सड़कों पर उमड़ी प्रवासी श्रमिकों की भीड़ किसी को भी परेशान करने के लिए काफी थी। इस पलायन के बाद अनगिनत सवाल सामने थे.. कि इनका क्या होगा? भोजन-पानी की व्यवस्था कैसे होगी? ये घर तक कैसे पहुंचेंगे? इन्हें संक्रमण से कैसे बचाया जायेगा?

जब पूरा देश इन चिंताओं में घिरा था तब कुछ राज्य सरकारें अपनी राजनीति में व्यस्त थीं, उन्हें न तो भूखे पेट सो रहे श्रमिकों की चिंता थी न ही बिना दूध के रोते बच्चों को। इन राज्यों को पैदल चल रहे श्रमिकों के पैरों के छाले नहीं दिखे लेकिन राजनीति करने का एक अवसर दिखा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर उसके द्वारा शासित कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक ने कोरोना काल में श्रमिकों को लेकर केंद्र सरकार पर अनगिनत आरोप लगाये लेकिन समय के साथ सच्चाई बाहर आ ही गयी।

बात प्रियंका गाँधी के सैंकड़ों बसें भेजने की दावों की हो या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ट्रेन उपलब्ध न करवाने के आरोपों की, जनता ने चुप चाप सब देखा और समझने की कोशिश करती

रही कि कौन उसके हितों की रक्षा करने में सक्षम है।

जैसे हीं श्रमिकों के पलायन की शुरुआत हुई वैसे ही केंद्र सरकार तुरंत एक्शन में आ गयी थी, जगह-जगह श्रमिकों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करवाई गयी। जो छात्र अपने राज्यों से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे थे उन्हें उनके घर भेजने की व्यवस्था की गई और मध्यप्रदेश की सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि छात्र जहां पर रुके हुए हैं वहां उन्हें कोई असुविधा ना हो। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में फंसे छात्रों को घर भेजने के लिए ट्रेन की व्यवस्था की।

भारतीय रेलवे के यूट्यूब चैनल पर उपस्थित एक वीडियो पूरी स्थिति को स्पष्ट कर देता है।यह विडियो हबीबगंज से रीवा के लिए चलाई गई ट्रेन का है जिससे श्रमिक और छात्र अपने घरों को जा रहे हैं। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्रशासन द्वारा रेलवे स्टेशन में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए गोले बनाए गए हैं, और नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस की भी तैनाती की गई है।

प्लेटफार्म पर जाने से पहले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है ताकि अगर किसी में कोरोना वायरस के लक्षण हों तो उसे ट्रेन पर चढ़ने से पहले पहचाना जा सके। प्लेटफार्म के बाहर ही सरकार एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा यात्रियों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई है।

वीडियो में एक महिला यात्री को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि "सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। थर्मल स्कैनिंग की जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है और सभी यात्रियों के लिए भोजन की अच्छी व्यवस्था की गई।" इस यात्री द्वारा कही गयी बातें हीं विपक्ष द्वारा लगाये गए सभी आरोपों का जवाब है।

उसी वीडियो में में एक अन्य यात्री बता रहे हैं कि वह 'दो महीने से लॉकडाउन के कारण भोपाल में फंसे थे। उन्हें उनके घर भेजने के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई और निश्चित तिथि से तीन-चार दिन पहले ही उन्हें उनके ट्रेन की सूचना दे दी गई थी।' यात्री कह रहे हैं कि खाने की अच्छी व्यवस्था की गई है और हम सब इस से बहुत खुश हैं कि हम आखिरकार अपने घर जा रहे हैं। इस यात्री के चेहरे से झलकती घर जाने की ख़ुशी ही प्रशासन के लिए पारितोषिक और केंद्र सरकार के सुप्रबंधन का प्रमाण है।

लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी सेवाओं में लगे डॉक्टर और पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का पालन तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही देशभर से कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आयीं जिन्होंने यह

दिखाया कि हमारे पुलिसकर्मी और डॉक्टर अपने कर्तव्यों के साथ मानवीय संवेदना को लेकर भी संवेदनशील हैं।

जबलपुर रेलवे स्टेशन पर बनाए गए एक वीडियो में देखने को मिला कि एक पुलिस वाला अपने घर वापस जा रहे प्रवासी श्रमिकों के साथ आ रही एक बच्ची को चप्पल दे रहा है। यह बच्ची शायद कई किलोमीटर दूर से चलकर आई होगी लेकिन सरकार द्वारा रेलवे स्टेशन पर की गई व्यवस्थाओं के कारण उसकी घर की दूरी कम हो गई, अब उसे और पैदल चलना नहीं पड़ेगा। उसके पैदल चलने के इन्हीं जख्मों पर पुलिस कर्मी की यह संवेदनशीलता मरहम लगाने का काम कर रही है।

सरकार और प्रशासन के साथ भारत का समाज भी लॉकडाउन के दौरान बढ़-चढ़ कर आगे आया। प्रधानमंत्री ने अपने 15 अगस्त के भाषण में कहा था कि देश में सिर्फ दो तरह के लोग हैं। एक जो जरुरतमंद हैं और दूसरे वो जो इन जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। कोरोना के इस संकट में प्रधानमंत्री का यह वाक्य साक्षात् हो गया, समाज का हर सक्षम व्यक्ति किसी न किसी तरह जरुरतमंदों की मदद में लगा था। कोई भोजन पानी की व्यवस्था में लगा था, तो कोई दवाइयों की चिंता कर रहा था।

कई मकान मालिकों ने किरायेदारों से किराया नहीं लिया तो कई लोग एक फ़ोन कॉल पर हर तरह की सहायता के लिए उपलब्ध रहे। सरकार और समाज के आपसी सहयोग के कारण ही यह संभव हो पाया कि इतनी बड़ी संख्या में हुए पलायन के बावजूद स्थितियां नियंत्रण में रहीं और कोई बड़ी अनहोनी घटना नहीं हुई।

लेकिन शर्मनाक है कि जब सरकार और समाज सेवा कार्यों में व्यस्त थे तब देश का राजनीतिक विपक्ष बयानबाजी और राजनीति में व्यस्त था, देश महामारी झेल रहा था और विपक्ष पार्टी पॉलिटिक्स में उलझा था। भारत का समाज जब कभी भी कोरोना के इस संकट को याद करेगा तो वह सरकार की संवेदनशीलता, कर्तव्यपरायणता और व्यवस्था के साथ विपक्ष की इस काली छाया को भी जरुर याद रखेगा।

वीडियो लिंक - https://youtu.be/vb93DCjYRUI

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

प्रवासी मजदूरों के लिए संजीवनी सिद्ध हो रहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान

सतीश सिंह

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को शुरू की थी। इस अभियान को शुरू हुए लगभग 50 दिन हुए हैं। लेकिन इतने समय में ही इस अभियान के तहत लगभग 15 करोड़ कार्यदिवस सृजित किये जा चुके हैं। यह इस अभियान की सफलता को दर्शाता है।

कोरोना महामारी के कारण अप्रैल, मई और जून महीनों में करोड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूरों एवं कामगारों को अपने गाँव लौटना पड़ा था। घर वापसी के बाद अधिकांश मजदूरों एवं कामगारों को अपने गाँव में रोजगार नहीं मिल रहा था और अधिकतर लोगों की जमा-पूँजी तालाबंदी के 15 दिनों के अंदर ही समाप्त हो चुकी थी।

इसी बीच, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का आगाज किया, जो प्रवासी मजदूरों एवं कामगारों के लिये संजीवनी बन गयी है। आज इस अभियान की मदद से करोड़ों प्रवासी मजदूर एवं कामगार अपना जीवनयापन कर रहे हैं।

मौजूदा समय में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर एवं कामगार 6 राज्यों, मसलन, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और झारखण्ड के रहने वाले हैं। इसलिये, इस अभियान को इन राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक प्रवासी मजदूरों एवं कामगारों को रोजगार देने के लिये मिशन की तरह चलाया जा रहा है।

इस अभियान की जद में बिहार के 32 जिले, उत्तरप्रदेश के 31 जिले, मध्यप्रदेश के 24 जिले, राजस्थान के 22 जिले, ओडिशा के 4 जिले और झारखंड के 3 जिले हैं। सच कहा जाये तो इस अभियान को चलाना बहुत ही जरूरी था, अन्यथा करोड़ों की संख्या में मजदूरों एवं कामगारों को भूखे मरने की

नौबत आ जाती।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान को ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, खनन मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सीमा सड़क मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के सयुंक्त प्रयासों से चलाया जा रहा है। इन 12 मंत्रालयों को इस अभियान से इसलिये जोड़ा गया है, ताकि रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रों की व्यापकता में वृद्धि हो।

इन मंत्रालयों के तहत आने वाले क्षेत्रों में इस अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों एवं कामगारों को रोजगार दिया जा रहा है। उदहारण के तौर पर इस अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण, सामुदायिक केंद्र का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण व मरम्मत, ग्रामीण आवास का निर्माण, बागवानी लगाना एवं उसका रखरखाव, जल संरक्षण से जुड़े कार्य, मिट्टी कटाई के काम, कुओं का निर्माण, वृक्षारोपण का काम, ग्रामीण कनेक्टिविटी का काम, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े कार्य, खेत एवं तालाबों का निर्माण, पशु शेड के तहत पोल्ट्री, बकरी, गाय व भैंस के लिये शेड का निर्माण, वर्मी-कम्पोस्ट संरचनाओं का निर्माण आदि कार्य प्रवासी मजदूरों एवं कामगारों के द्वारा किया जा रहा है। जहाँ पर पंचायत भवन नहीं है, वहाँ पंचायत भवन का निर्माण भी प्रवासी मजदूरों एवं कामगारों के द्वारा किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अबतक 12,072 करोड़ रूपये की राशि प्रवासी मजदूरों या कामगारों को रोजगार देने में खर्च की जा चुकी है और लगभग 15 करोड़ कार्यदिवस इस अभियान के अंतर्गत सृजित हो चुके हैं।

इस अभियान की मदद से 1,751 स्वच्छता परिसर, 1,43,951 ग्रामीण आवास, 12,968 पशुओं के लिये शेड, 7,662 कृषि तालाब, 2,806 बकरियों के लिये शेड, 51,984 जल संरक्षण एवं मिट्टी की कटाई के कार्य, 36,266 हेक्टेयर में वृक्षारोपण, 3,074 श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन से जुड़ी गतिविधियां, 9,219 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन आदि परिसंपत्तियां सृजित हुई हैं।

रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अब तक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के 116 चिह्नित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 737 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च की है, जिससे 2,20,413 कार्य दिवस का सृजित हुए हैं।

रेलवे ने इस अभियान के तहत 160 बुनियादी संरचना परियोजनाओं को चिह्नित किया है। माना जा रहा है कि अक्टूबर महीने के अंत तक रेलवे के प्रयासों से लगभग आठ लाख कार्य दिवस सृजित होंगे,

जिसपर करीब 1,800 करोड़ रुपये की राशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार 125 दिनों के अंदर सरकार लगभग 25 योजनाओं को 116 जिलों तक पहुँचाना चाहती है। सरकार का लक्ष्य है कि इन सभी योजनाओं का लाभ प्रवासी मजदूरों एवं कामगारों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत दिया जाये।

गरीब कल्याण रोजगार का ऑनलाइन वेब पोर्टल बनाया गया है। यह वेब पोर्टल प्रवासी मजदूरों एवं कामगारों को इस अभियान की जिलावार जानकारी प्रदान करता है। साथ ही, यह 6 राज्यों के 116 जिलों में चल रहे कार्यों को पूरा करने की प्रगति की निगरानी रखने में भी मदद करता है।

इस योजना का फ़ायदा उठाने के लिये वेब पोर्टल पर प्रवासी मजदूरों एवं कामगारों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। सरकार की योजना इस अभियान को सफल बनाने के लिये लगभग 50 हज़ार करोड़ रूपये खर्च करने की है, ताकि अधिक से अधिक प्रवासी मजदूर एवं कामगार इस अभियान से लाभान्वित हो सकें।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की मदद से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिये ग्रामीण उत्पादों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। चिन्हित 6 राज्यों के जिलों में ऐसे अनेक स्थानीय उत्पाद हैं, जिन्हें बढ़ावा देने से कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा एवं लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान को सफल बनाने के लिये सभी हितधारकों एवं 12 मंत्रालयों के बीच समन्वय बनाकर कार्य किया जा रहा है। इस अभियान के तहत मजदूरों एवं कामगारों को उनकी कार्यकुशलता के आधार पर काम दिया जा रहा है।

सरकार चाहती है कि सभी मजदूरों एवं कामगारों को उनके गुण, कुशलता एवं विशेषज्ञता के आधार पर काम दिया जाये। ऐसा करने से मजदूर एवं कामगार अपना सर्वश्रेष्ठ दे पायेंगे और इससे किये जाने वाले कार्यों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता दोनों में इजाफा होगा।

कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान से प्रवासी मजदूरों एवं कामगारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रही है। लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस तरह, सरकार के रोजगार सृजन वाले इस अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति में इजाफा हो रहा है साथ ही साथ कोरोना महामारी के नकारात्मक असर को भी कम करने में मदद मिल रही है।

(लेखक भारतीय स्टेट बैंक के कॉरपोरेट केंद्र मुंबई के आर्थिक अनुसंधान विभाग में कार्यरत हैं। आर्थिक मामलों के जानकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

अब जल शक्ति घर लौटे कामगारों का बनेगा आधार

नेशनलिस्ट टीम

प्र भारत सरकार ने अपने महतवाकांक्षी प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन को और तेज कर दिया है। कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में इस प्रोजेक्ट को न सिर्फ कामगारों के लिए जीवन दायक मिशन के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूती देने में भी यह अहम भूमिका निभा सकता है।

दरअसल, महामारी के चलते लाखों की तादाद में प्रवासी कामगार अपने घरों को लौट गए हैं। रोजगार के अभाव और परिवार के पोषण की जिम्मेदारी इनके लिए चुनौती बनी हुई है। ऐसे में ग्रामीण विकास की ऐसी योजनाएं उनके जीवन को एक आधार देती दिख रही हैं।

अबतक ग्रामीण अंचलों में चल रहे मनरेगा और गरीबों की आवास योजनाओं ने लोगों को रोजी-रोटी के साथ इज्जत से जीना सिखाया है। अब जब केंद्र सरकार 'जल जीवन मिशन' को तेज करने का मन बना चुकी है, तो निश्चित रूप से घर लौटे इन हताश कामगारों के लिए यह रोजगार का बेहतरीन मौका साबित होगा। यही नहीं, ग्रामीणों के जल की समस्या को भी दूर करने में भी यह योजना मील का पत्थर साबित हो सकती है।

विचार करें तो यह ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूती देने का बेहतरीन मौका है, जिसमें घर आए इन कामगारों की भूमिका अहम होगी। इस बात को केंद्र सरकार अच्छी तरह समझ रही है और यही मौका देखकर इस योजना को युद्ध स्तर पर चालू करने के प्रयास में है। बता दें कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन पर काम शुरू कर दिया है।

ताजा हालात के मद्देनजर यह मिशन कई राज्यों के लिए राहत देने वाला होगा। इससे राज्यों की पेय जल की समस्या का हल भी निकाला जा सकेगा, साथ ही घर वापस गए कामगारों को रोजगार भी दिया जा सकेगा।

यही नहीं, योजना में यह भी निर्णय लिया गया है कि पुरानी लंबित पड़ी ऐसी परियोजनाओं को भी

इसके साथ शामिल किया जाए, जिनके लिए कुशल कामगारों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में पलायन कर लौटे कामगारों की यहां खासा मांग रहेगी। बताते चलें कि शहरों से अपने अपने घरों की तरफ पलायन करने वाले ग्रामीणों में 40 प्रतिशत से अधिक वह कामगार हैं जो शहर के कंस्ट्रक्शन एरिया में काम करते थे और रोजी रोटी कमाते थे।

15वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक, ग्रामीण स्थानीय निकायों को 60,750 करोड़ की ग्रांट मिलनी है, जिसका पचास प्रतिशत से ज्यादा भाग जलापूर्ति और स्वच्छता पर खर्च किया जाएगा। यह मिशन ग्राम पंचायतों, मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जैसी विभिन्न योजनाओं को मिले इस ग्रांट के उपयोग के तहत किया जाएगा। पूरी योजना लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ की है जिसमें केंद्र को दो लाख दस हजार और राज्यों को डेढ़ लाख करोड़ योगदान स्वरूप दिया जाएगा।

याद दिलाते चलें कि पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर जल योजना की घोषणा की थी। इसलिए भी यह योजना केंद्र के लिए बेहद अहम है। महामारी के दौर में यह योजना राज्यों की जल समस्या का भी निदान करेगी और ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षित कामगारों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगी।

इस योजना की यदि मनरेगा से तुलना की जाए तो मनरेगा सिर्फ ग्रामीणों के लिए रोजगार का अवसर देता है, जबकि जल जीवन मिशन रोजगार के अलावा बाजार में मांग बढ़ाएगा तथा क्षेत्र का स्थायी ढांचा भी खड़ा करेगा।

यदि इस मिशन में योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए तो जल्द ही लोगों को पर्याप्त मात्र में स्वच्छ पेय जल की सुविधा मिलेगी और देशभर में इस पूरे सिस्टम को मजबूत बनाने पर काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना की गंभीरता को इस बात से भी आंका जा सकता है कि इसके लिए अलग से आम बजट आवंटन किया गया है, जिससे मिशन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

जहां तक गुणवत्ता की बात है, तो गांव व पंचायत स्तर पर जल की जांच के लिए किट मुहैया की जाएगी। इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने की भी योजना है। यह युवक गांव के ही होंगे और इनकी संख्या पांच होगी।

जानना रोचक होगा कि दरअसल हमारे देश में अप्रैल 2019 तक 19.04 करोड़ घरों में से 3.23 करोड़ घरों में नल से सप्लाई पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना सलीकेबार ढंग से अपना काम कर रही है और इससे पेय जल की आपूर्ति से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो पाएंगे।

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

9, Ashoka Road, New Delhi- 110001

Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org,

@spmrfoundation

Phone:011-23005850